

गौरवशाली भारत

दिल्ली से प्रकाशित

R.N.I. NO. DELHIN/2011/38334

वर्ष: 11

अंक: 201

पृष्ठ : 08,

नई दिल्ली, बुधवार, 02 फरवरी 2022

मूल्य: 1.50/-

मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का तीसरा बजट आज

दुश्वारियों के बीच राहत की आस

मानसून सामान्य रहे और तेल की कीमतें 70-75 डॉलर प्रति बैरल के बीच रहेंगी

नई दिल्ली, एजेंसी।

वर्ष 2022-23 में देश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर आठ से साढ़े आठ प्रतिशत रह सकती है, बशर्ते कोरोना महामारी भयंकर रूप धारण न करे, मानसून सामान्य रहे और तेल की कीमतें 70-75 डॉलर प्रति बैरल के बीच रहेंगी। दरअसल यह अनुमान आर्थिक सर्वेक्षण में लगाया गया है। सर्वेक्षण ने स्पष्ट रूप से वित्तमंत्री के सामने चुनौतियों की फेहरिस्त पेश कर दी है। देश ने बजट से बहुत सी उम्मीदें लाई हैं, लेकिन कोरोना महामारी के कारण उपजे परिस्थितियों के कारण सरकार के पास विकल्प सीमित हैं। मोदी सरकार के पास कड़े फैसले लेने के लिए मंगलवार को पेश होने



वाला बजट ही बचा है। अगला बजट 2024 के आम चुनाव को ध्यान में रखकर लोकलुभावन बजट पेश किया जाएगा। इस बार आम लोगों ने बजट से बड़ी उम्मीदें लगायी हैं, लेकिन सरकार के पास विकल्प सीमित हैं। निश्चित तौर पर देश की अर्थव्यवस्था में तेजी दिख रही है, लेकिन राजकोषीय घाटा और चालू खाता घाटा चिंता का विषय है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में मंगलवार सुबह 11 बजे लगातार चौथा बजट पेश करेंगी। 2020 से वह कोरोना महामारी के कारण ध्वस्त हुई

अर्थव्यवस्था को संभालने में व्यस्त है। पिछले बजट में भी उन्होंने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए अनेक प्रयास किये थे, उनके कुछ सकारात्मक परिणाम तो दिखे लेकिन उम्मीद के अनुसार नहीं दिखे। इस बार उनसे ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि इस बार लॉक डाउन नहीं लगाया गया। जीएसटी की उग्राही भी बढ़ते हुए क्रम में है और आयात करने की बालों की संख्या भी बढ़ी है। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती अर्थव्यवस्था की ग्रेथ को रोजगारोन्मुख बनाना है, क्योंकि अभी तक जो वृद्धि देखी गई

बजट सत्र को फलदायी बनाएं सांसद: पीएम

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि चुनाव का लोकतंत्र में अपना स्थान है और वह प्रक्रिया जारी रहेगी लेकिन पूरे वर्ष का खाका खींचने वाला संसद का बजट सत्र बहुत महत्वपूर्ण है। बजट सत्र के पहले दिन संवाददाताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने सभी सांसदों और राजनीतिक दलों से इस सत्र को फलदायी बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा यह बात सही है कि बार-बार चुनाव के कारण सत्र भी प्रभावित होते हैं, चर्चाएं भी प्रभावित होती हैं।

वह देश के लिहाज से उचित है लेकिन उससे ज्यादा रोजगार पैदा नहीं हो रहे हैं। दूसरी चुनौती महंगाई पर काबू पाना है। महंगाई के कारण सारा देश त्रस्त है। उनके सामने यह भी चुनौती है कि पांच राज्यों के चुनाव के समय से कड़े कदम उठाने वाला बजट कैसे पेश किया जाए। उनके कड़े कदमों से भाजपा को नुकसान हो सकता है। उनके सामने चुनौती राजकोषीय घाटा कम करने की है। पिछले साल राजकोषीय घाटा साढ़े नौ प्रतिशत से अधिक था, जो 2021-22 में घटकर 7 प्रतिशत रहने का अनुमान है लेकिन सरकार ने राजकोषीय घाटा चार से पांच प्रतिशत के बीच रखने का लक्ष्य

रखा था। इसी तरह चालू खाता घाटा भी लगातार बढ़ रहा है, यानि निर्यात से ज्यादा आयात पर खर्च बढ़ रहा है। आर्थिक समीक्षा ने अनुमान लगाया है कि वर्ष 2022-23 में आर्थिक वृद्धि दर 8-8.5 प्रतिशत रह सकती है, बशर्ते कोरोना महामारी लेकर आगे कोई आर्थिक गतिरोध नहीं पैदा होगा, मानसून सामान्य रहेगा, बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के केंद्रीय बैंकों द्वारा नकदी प्रवाह को कम करने का प्रस्तावित काम व्यवस्थित ढंग से होगा, तेल की कीमतें 70-75 डॉलर प्रति बैरल के बीच रहेंगी तथा वर्ष के दौरान आयात श्रृंखलाओं की रुकावटें धीरे-धीरे कम हो जाएगी।

ईडी के जेडी राजेश्वर का वीआरएस मंजूर

आज का दिन हमें बापू की शिक्षाओं की याद दिलाता है, नेशनल वॉर मेमोरियल का भी किया जिक्र

लखनऊ, एजेंसी।

प्रवर्तन निदेशालय के संयुक्त निदेशक रहे राजेश्वर सिंह का वीआरएस सोमवार को स्वीकार हो गया। अब वह राजनीति में अपनी किस्मत आजमाएंगे। जल्द ही वह भाजपा में शामिल होंगे और सुल्तानपुर सदर या लखनऊ की सरोजनी नगर विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार हो सकते हैं।

राजेश्वर सिंह 1996 में पीपीएस अधिकारी चुने गए थे। सीओ के पद पर रहते उनकी छवि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की बनी। इसके बाद 2009 में वह ईडी में चले गए। उनके परिवार और रिश्तेदारों में कई अधिकारी हैं। पत्नी लक्ष्मी सिंह लखनऊ रेंज की आईजी हैं। बहनोई राजीव कृष्ण एड्वोकी आगरा जेल हैं। एक और बहनोई आईपीएस रहे, उन्होंने भी वीआरएस लिया था। एक भाई और एक बहन अयकर में अधिकारी हैं।

राजेश्वर सिंह का 11 वर्ष का सेवाकाल शेष था। उन्होंने इसकी



सूचना खुद ही सोशल मीडिया पर दी। अपने संदेश में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया है।

वर्ष 1997 बैच के पीपीएस अधिकारी रहे राजेश्वर सिंह ने सोशल मीडिया पर सेवाकाल का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि 24 वर्षों का कारवां एक पड़ाव पर आज रुका है। दस वर्ष पीपीएस में नौकरी करने और 14 वर्ष ईडी में सेवा देने के बाद अब संन्यास ले रहा हूँ। वह वर्ष 2007 में ईडी में प्रतिनियुक्ति पर चले गए थे। वहां उन्होंने कई अहम घोटाले की जांच की। इसमें 2जी स्मैकटम आवंटन घोटाला, अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील, एयरटेल मैक्सिस घोटाला, आम्रपाली घोटाला, नोएडा पॉंजी स्कीम घोटाला, गोमती रिवर फंट

घोटाला आदि शामिल है। उन्होंने बताया कि ईडी में तैनाती के दौरान घोटालेबाज नेताओं, नौकरशाहों, बाहुबलियों और माफिया से उनकी अवैध कमाई से अर्जित 4000 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्तियों को जब्त किया।

राजेश्वर सिंह पांच साल के लिए प्रतिनियुक्ति पर प्रवर्तन निदेशालय गए थे। पहले उन्हें दो साल का विस्तार दिया गया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ईडी में ही स्थायी हो गए। वर्तमान में वह बतौर संयुक्त निदेशक लखनऊ जेल का काम देख रहे थे। उन्होंने अपने संदेश में भाजपा के शीर्ष नेताओं का जिक्र करते हुए लिखा है कि भारत को विश्व शक्ति और विश्व गुरु बनाने का जो संकल्प लिया है, उसका मैं भी भागीदार बनना और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहता हूँ।

खास खबर

जहरीली शराब कांड के चार आरोपित मार में फार्म हाउस से गिरफ्तार

श्यांपुर। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में हुए जहरीली शराब कांड के चार आरोपितों को मध्य प्रदेश पुलिस की मदद से यहां के फार्म हाउस से गिरफ्तार किया है। श्यांपुर के बड़ौदा स्थित गिल फार्म हाउस में आरोपितों के होने की पुलिस को सूचना मिली थी। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सुंदरनगर थाने से इंस्पेक्टर कमलेश टीम के साथ यहां सिटी कोतवाली पहुंचे। उन्होंने बताया कि मंडी जिले में जहरीली शराब पीने से सात लोगों की मौत हो गई थी, वहीं 12 लोग गंभीर बीमार हो गए थे। आरोपित घटना के बाद से ही फरार चल रहे थे। आरोपितों की लोकेशन पहले राजस्थान के जयपुर में मिली थी, बाद में श्यांपुर जिले में मिली रही है। पुलिस टीम ने गिल फार्म हाउस में शराब कांड के आरोपित 43 वर्षीय गुरदेव सिंह थाना नयनादेवी जिला बिलासपुर, 24 वर्षीय राकेश सिंह निवासी पूना, 34 वर्षीय वैदित जिला बिलासपुर, अनिल निवासी थाना पिपलोदकर जिला कांगड़ा को गिरफ्तार किया है।

सुप्रीम कोर्ट हरियाणा के संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अदमानना याचिका पर शीघ्र सुनवाई को सहमत

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय गुरुग्राम के सार्वजनिक पार्कों में जुमे (शुक्रवार) की नमाज के आसपास हिंसक घटनाओं को रोकने में कथित विफलता के लिए हरियाणा के संबंधित अधिकारियों के खिलाफ दायर अदमानना याचिका पर शीघ्र सुनवाई को उपयुक्त पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने के लिए सहमत दी। वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने विशेष उल्लेख के तहत इस याचिका पर शीघ्र सुनवाई की गुहार लगाई थी। उन्होंने विभिन्न दलीलें देते हुए इस याचिका पर शीघ्र सुनवाई की आवश्यकता बताई है। अदीब ने अपनी याचिका में हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव संजीव कौशल (आईएसएस) और पुलिस महानिदेशक पी. के. अग्रवाल (आईपीएस) के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इन शीर्ष अधिकारियों पर सांप्रदायिक और हिंसक प्रवृत्तियों को रोकने में पूरी तरह से निष्क्रियता का आरोप लगाया। राज्य सरकार ने दिसंबर 2021 में स्थानीय निवासियों के विरोध के बाद गुरुग्राम के सार्वजनिक पार्कों में मुसलमानों को शुकुवार की नमाज पर प्रतिबंध लगा दिया था।

यूपी में पांच साल पहले दंगाई ही थे कानून : पीएम मोदी

- राज्य सरकार ने बदले हालात
- अब जनता नहीं चाहती पुराने दिनों की वापसी
- जब दंगे रहे थे तब सपा सरकार मना रही थी उत्सव

लखनऊ, एजेंसी।

उत्तर प्रदेश में 18वीं विधानसभा के लिए सात चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण के लिए वोटिंग 10 फरवरी को होगी। इस बीच बीजेपी बीजेपी के सबसे बड़े ब्रांड और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूपी में एंट्री हो चुकी है। पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जिक्र करते हुए संबोधन की शुरुआत की। पीएम मोदी ने शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, सहारनपुर और गौतमबुद्ध नगर के मतदाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि, पश्चिम उत्तर प्रदेश की ये वो धरती है जिसने 1857 की क्रांति में देश को एकजुटता का संदेश दिया था, कमल के फूल और रोटी ने हमेशा देश को बांटने



वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया। हम एकजुट रहेंगे तो कोई हमें कभी परास्त नहीं कर पाएगा।

प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि, जब मैं पांच साल पहले चुनाव के समय पश्चिमी यूपी में आया था, तो आपसे कहा था कि यूपी के विकास के लिए हम कोई कोर-कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। इन पांच वर्षों में योगी जी के नेतृत्व में, यूपी सरकार ने पूरी ईमानदारी और निष्ठा से आपकी सेवा करने का, यूपी के विकास का प्रयास किया है। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि, 5 साल पहले दंगा और दंगाई ही कानून थे, उन्हीं का कड़ा ही शासन का आदेश था। पहले व्यापारी लुटता था, बेटी घर से बाहर निकलने में संभराती थी और माफिया, सरकारी संरक्षण में खुलेआम धन कमा रहे थे। अब यूपी के विकास का आदेश था, पहले वाली सरकार उत्सव मना रही थी।

मुलायम की कर्मभूमि से मैदान में उतरे अखिलेश

- पचां भरने के कुछ ही देर बाद सत्यपाल सिंह बटोल का बीजेपी ने नामांकन कराया कर सभी को चौंका दिया

इटावा, एजेंसी।

यादव बाहुल्य मैनुपुरी की करहल विधानसभा सीट से सोमवार को समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव के सोमावार को अपना नामांकन दाखिल किया। उनके पचां भरने के कुछ ही देर बाद केन्द्रीय राज्य मंत्री सत्यपाल सिंह बटोल का बीजेपी ने नामांकन कराया कर सभी को चौंका दिया। केन्द्रीय मंत्री को अखिलेश यादव के खिलाफ उतारने के पीछे बीजेपी की रणनीति थी। बीजेपी ने यह संकेत दे दिया कि वह किसी भी नेता को %वाकओवर% देने के मूड में नहीं है। इस बार मुकाबला सपा और भाजपा के बीच है तो अखिलेश को रोकने की रणनीति भी इसे माना जा रहा है।

अखिलेश ने आज करहल विधानसभा सीट के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। पहले ऐसी संभावनाएं जताई जा रही थी कि



करहल की विधानसभा सीट को सपा या फिर मुलायम परिवार के लिए अजेय और जीवन दायनी मानी जाती है। अखिलेश यादव कहते हैं हू करहल

भाजपा इस सीट से अखिलेश को वाकओवर देने की तैयारी में है लेकिन दोपहर बाद केन्द्रीय राज्य मंत्री एवं आगरा के सांसद अखिलेश सिंह बटोल अपना नामांकन करने आ पहुंचे। अब करहल विधानसभा की इस सीट पर कड़ा और संघर्षपूर्ण मुकाबले की उम्मीद जताई जाने लगी है। अखिलेश के मुकाबले भाजपा ने करहल विधानसभा सीट पर जिन केन्द्रीय राज्य मंत्री को चुनाव मैदान में उतारा है, वह कभी अखिलेश के पिता मुलायम सिंह यादव के सुरक्षा अधिकारी भी रह चुके हैं। अखिलेश मैनुपुरी मुख्यालय से जैसे ही नामांकन करके बाहर वापस निकले वैसे ही भाजपा उम्मीदवार के तौर पर एसपी सिंह बघेल भी अपना नामांकन करने के लिए आ पहुंचे। बटोल के नामांकन करने के बाद भाजपा के स्थानीय और राज्य स्तरीय नेता उत्साहित नजर आए। साल 2002 के अलावा भाजपा कभी भी करहल में चुनाव नहीं जीत सकी है।

(मुलायम सिंह यादव) की शैक्षिक और राजनीतिक कर्म भूमि रही है। यहां की जनता नेताजी को ना केवल पसंद करती है बल्कि उनके परिवार से भी उनका बेहद लगाव बना हुआ है और इसी वजह से जब जब यहां चुनाव हुआ है तो सपा उम्मीदवारों को रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल हुई है।

करहल का चुनाव यहां की जनता लड़ेगी और रिकॉर्ड मतों से जिता कर उनको विधानसभा में भेजने का काम करेगी। विधानसभा के चुनाव में खुद उनको कई और क्षेत्रों में भी जाना पड़ेगा इसलिए उन्होंने अपने चुनाव को जनता के हवाले कर दिया है। अब जनता को नर्णय लेना है कि वह उनको कितने मतों से विजई बनाने का काम करते हैं। इटावा से मैनुपुरी तक समाजवादियों का गढ़ माना जाता है। इलाके में मुलायम सिंह के प्रति भाजपा की गहरी पैठ दिखती है जबकि भाजपा का जनाधार यहां बेहद कम है।

नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 126 से घटकर 70 हुई : रामनाथ कोविंद

- जम्मू-कश्मीर में सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता

नई दिल्ली, एजेंसी।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज कहा कि सरकार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों तथा पूर्वोत्तर के विकास के लिए प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है जिसके चलते देश में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या घटकर 70 रह गयी है।

कोविंद ने सोमवार को संसद के बजट सत्र के पहले दिन केन्द्रीय कक्ष में दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए अनेक ठोस कदम उठाये हैं और इनका असर दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा, सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से आज देश में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 126 से घटकर 70 रह गई है। पूर्वोत्तर के विकास के लिए सरकार के प्रयासों तथा योजनाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, मेरी सरकार पूर्वोत्तर के सभी राज्यों - अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय,



मिजोरम, नगालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के सतत विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इन राज्यों में हर स्तर पर बुनियादी और आर्थिक अवसरों का विकास किया जा रहा है। रेल और हवाई कनेक्टिविटी जैसी सुविधाओं का सपना पूर्वोत्तर के लोगों के लिए अब साकार हो रहा है। यह देश के लिए गर्व का विषय है कि पूर्वोत्तर राज्यों की सभी राजधानियां मेरी सरकार के प्रयास से अब रेलवे के नक्शे पर आ रही हैं। उन्होंने कहा कि इंदरनगर के होलोगी में एक नए एयरपोर्ट की स्थापना की जा रही है। हाल ही में त्रिपुरा राज्य के महाराज बीर बिक्रम एयरपोर्ट में एक नया और आधुनिक टर्मिनल खोला गया है। पूर्वोत्तर का यह विकास भारत की विकास यात्रा

का एक स्वर्णिम अध्याय सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले ही 21 जनवरी को मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा की स्थापना के 50 साल पूरे हुए हैं। आज की 75 साल पूरे होने के साथ इन राज्यों की यात्रा भी हमें विकास के नए संकल्पों के लिए प्रेरित कर रही है।

राष्ट्रपति ने कहा कि पूर्वोत्तर में शांति स्थापना के लिए सरकार के प्रयासों को ऐतिहासिक सफलता मिली है। अभी कुछ महीने पहले ही कार्बी-आंगलों के दशकों पुराने विवाद को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार, असम की राज्य सरकार एवं कार्बी समूहों के बीच समझौता हुआ है। इससे इस क्षेत्र में शांति और खुशहाली का एक नया अध्याय शुरू हुआ है।

टीकाकरण अभियान में एक सौ 66 करोड़ तीन लाख से अधिक कोविडरोधी टीके लगये जा चुके

नई दिल्ली, एजेंसी। पिछले 24 घंटों में 28 लाख से अधिक वैक्सीन की खुराक देने के साथ ही भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 166.03 करोड़ से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 1,81,83,260 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है। पिछले 24 घंटों में 2,62,628 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों (महामारी की शुरुआत के बाद से) की कुल संख्या बढ़कर 3,89,76,122 हो गई है। नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 94.37 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटे में 2,09,918 नए मरीज सामने आए हैं। वर्तमान में 18,31,268 सक्रिय रोगी हैं। वर्तमान में ये सक्रिय मामले देश के कुल पुष्टि वाले मरीजों का 4.43 प्रतिशत है।

देश भर में जांच क्षमता का विस्तार लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में कुल 13,31,198 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 72.89 करोड़ जांच की गई हैं। देश भर में जांच क्षमता को बढ़ाया गया है, साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 15.75 प्रतिशत है, दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 15.77 प्रतिशत है।

देश में किसानों को सबसे अधिक दिल्ली में मिल रहा मुआवजा : केजरीवाल

- 20 हजार रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से पूरे देश में किसानों को सबसे ज्यादा मुआवजा दिल्ली में मिल रहा

नई दिल्ली, एजेंसी।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बेमौसम बारिश से खराब हुई फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए आज किसानों को मुआवजा राशि का चेक सौंपा और कहा कि बेमौसम बारिश की वजह से किसानों की फसल खराब हो गई थी। उनके नुकसान की भरपाई के लिए हमने मुआवजा राशि देना शुरू कर दिया है। 20 हजार रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से पूरे देश में किसानों को सबसे ज्यादा मुआवजा दिल्ली में मिल रहा है। इसके अलावा, जनवरी के सस्से की फसल खराब हो गई थी। उसका मुआवजा देने के लिए मैंने सर्वे का आदेश दे दिया है। हमारी सरकार बनने से पहले दिल्ली के शासन व्यवस्था से किसान पूरी तरह से गायब



था। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर बारिश से 70 फीसद से कम फसल नुकसान हुई है, तो 70 फीसद और 70 फीसद से ज्यादा फसल नुकसान हुई है, तो 100 फीसद मुआवजा मिलेगा। पंजाब में भी कपास की फसल बर्बाद हुई है और पंजाब सरकार ने 12 हजार रुपए देने का ऐलान किया है, लेकिन अभी तक किसानों को पैसा नहीं मिला है। जिस देश या जिस राज्य के चुनाव में किसानों की इज्जत नहीं है, वो देश तरकी नहीं कर सकता। अरविंद केजरीवाल ने बीते अक्टूबर महीने में बेमौसम बारिश के चलते खराब हुई फसलों के लिए आज किसानों को मुआवजे का चेक वितरित किया। दिल्ली सचिवालय के ऑडिटोरियम में आयोजित मुआवजा वितरण कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री

के साथ राज्यस मंत्री कैलाश गहलोत, मुख्य सचिव विजय देव समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान किसानों ने सीएम अरविंद केजरीवाल को पाण्डे बांध कर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि

2013 की बात है। हमारी नई-नई पार्टी बनी थी। उस समय बेमौसम ओले पड़े थे। कई किसानों की फसलें बर्बाद हो गई थीं। उस समय स्वर्गीय शीला जी मुख्यमंत्री थीं। उनके पास कोई पत्रकार गया और बोला कि किसान बहुत दुखी हैं। ओले पड़े हैं, कुछ मुआवजा दिया जाएगा क्या? इस पर उनका जवाब था कि दिल्ली में खेती भी होती है क्या? 15 साल राज करने के बाद अगर कोई मुख्यमंत्री कहे कि दिल्ली में खेती होती है क्या? तो उसका अपमान हो गया। यह ये दिखाता है कि दिल्ली के पूरे शासन व्यवस्था से किसान किस तरह से गायब था।

चीन से पहले के मुकाबले कहीं 'अधिक स्पष्ट' खतरा: एफबीआई प्रमुख

वाशिंगटन। संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआई) के निदेशक क्रिस्टोफर रे ने चीन पर अमेरिकी अवधारणाएं और नवोन्मेष चुराने तथा हैकिंग के अभियान चलाने का आरोप लगाया और कहा कि पश्चिम को चीन की सरकार से पहले के मुकाबले कहीं "अधिक स्पष्ट" खतरा है।

एफबीआई निदेशक ने 'रोनाल्ड रीगन प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी' में अपने संबोधन में यह बात कही। उन्होंने चीन पर ये आरोप ऐसे वक्त लगाए हैं जब वह शीत ओलंपिक की मेजबानी करने जा रहा है। रे ने अपने संबोधन में यह स्पष्ट किया कि एक ओर जहां अमेरिकी विदेश नीति रूस और यूक्रेन के बीच तनाव से निपटने के रास्ते तलाश कर रही है वहीं वह दीर्घकालिक आर्थिक सुरक्षा के लिए चीन को सबसे बड़ा खतरा मान रही है।

एफबीआई की ओर से उपलब्ध कराए गए भाषण की प्रतिलिपि के अनुसार रे ने कहा, "जब हम अपनी जांचों का मिलावट करते हैं, तो पाते हैं कि



इनमें से दो हजार से अधिक मामले चीनी सरकार द्वारा हमारी सूचनाओं अथवा प्रौद्योगिकियों को चुराने से जुड़े हैं। ऐसा कोई देश नहीं है जो हमारी अवधारणाओं, नवोन्मेष, और आर्थिक सुरक्षा के समक्ष चीन जैसा व्यापक खतरा पैदा करता है।"

रे ने कहा, "चीन सरकार की आर्थिक जासूसी से नुकसान सिर्फ

इतना नहीं है कि उसकी कंपनियों अवैध रूप से प्राप्त तकनीक के आधार पर आगे बढ़ती हैं, बल्कि जब वे आगे बढ़ती हैं, तो वे हमारी कंपनियों और कर्मचारियों को पीछे धकेल देती हैं।"

चीन के अधिकारियों ने अमेरिका सरकार के आरोपों को हमेशा खारिज किया है।

रूस ने यूक्रेन पर मतदान से पहले 'अमेरिकी दबाव पर नहीं झुकने' पर भारत, चीन को धन्यवाद दिया

संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूक्रेन की स्थिति पर बैठक से पहले चीन के प्रक्रियागत मतदान के खिलाफ मत देने और इसमें भारत, केंन्या एवं गैर्बान के अनुपस्थित रहने पर संयुक्त राष्ट्र में एक रूसी राजनयिक ने "मतदान से पहले अमेरिकी दबाव के बावजूद डटे रहने" पर चारों देशों को शुक्रिया अदा किया।

भारत ने यूक्रेन सीमा पर "तनावपूर्ण हालात" को लेकर चर्चा के लिए होने वाली बैठक से पहले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में प्रक्रियागत मतदान में भाग नहीं लिया था।

संयुक्त राष्ट्र में रूस के प्रथम उप स्थायी प्रतिनिधि दमित्री पोलिस्की ने सोमवार को संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत लिन थॉमस-ग्रोनफील्ड के एक ट्वीट के जवाब में ट्विटर पर लिखा, "जैसा हमने उम्मीद की थी, यह एक जनसंपर्क हथकंडे के अलावा और कुछ नहीं था। यह



'मेगाफोन डिप्लोमेसी' (सीधे बातचीत करने के बजाय विवादित मामले में सार्वजनिक बयान देने की कूटनीति) का उदाहरण है। कोई सच्चाई नहीं, केवल आरोप और निराधार दावे।"

पोलिस्की ने कहा, "यह अमेरिकी कूटनीति का सबसे खराब स्तर है। अपने चार सहयोगियों चीन, भारत, गैर्बान और केंन्या का धन्यवाद, जो मतदान से पहले अमेरिकी दबाव के बावजूद डटे रहे।"

ग्रोनफील्ड ने कहा, "रूस की

आक्रामकता केवल यूक्रेन और यूरोप के लिए खतरा नहीं है, बल्कि यह अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के लिए भी खतरा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पर इसे जिम्मेदार बनाने का दायित्व है। यदि पूर्व साम्राज्यों को बल से अपने क्षेत्र फिर से हासिल करना शुरू करने का लाइसेंस मिल जाए, तो दुनिया के लिए इसका क्या अर्थ होगा? यह हमें एक खतरनाक मार्ग पर ले जाएगा।"

उन्होंने कहा, "हम स्वयं पर संकट आने से रोकने के लिए यूएनएससी में इस मामले को लेकर आए। यह रूस की सद्भावना की परीक्षा होगी कि क्या वह बातों की मेज पर बैठेगा और तब तक बना रहेगा, जब तक हम किसी सहमति पर नहीं पहुंच जाते? अगर वह ऐसा करने से इनकार करता है, तो दुनिया को पता चल जाएगा कि इसके लिए कौन और क्यों जिम्मेदार है।

बैठक से पहले परिषद के स्थायी और वीटो- अधिकार प्राप्त सदस्य

रूस ने यह निर्धारित करने के लिए एक प्रक्रियागत वोट का आह्वान किया था कि क्या खुली बैठक आगे बढ़नी चाहिए। अमेरिका के अनुरोध पर हुई बैठक के लिए परिषद को नौ मतों की आवश्यकता थी।

रूस और चीन ने बैठक के खिलाफ मतदान किया, जबकि भारत, गैर्बान और केंन्या ने भाग नहीं लिया। फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन सहित परिषद के 10 अन्य सदस्यों ने बैठक के चलने के पक्ष में मतदान किया।

बैठक में भारत ने रेखांकित किया कि "शांत और रचनात्मक" कूटनीति "समय की आवश्यकता" है और अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के व्यापक हित में सभी पक्षों द्वारा तनाव बढ़ाने वाले किसी भी कदम से बचना चाहिए।

यूक्रेन की सीमाओं के पास हजारों रूसी सैनिकों के एकत्र होने के बीच यूक्रेन संकट पर चर्चा करने के लिए 15 सदस्यीय परिषद ने बैठक

की थी। मास्को की कार्रवाई ने यूक्रेन पर आक्रमण की आशंकाओं को बढ़ा दिया है। रूस ने इस बात से इनकार किया कि वह हमले की योजना बना रहा है।

संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी एस तिरुमूर्ति ने परिषद में कहा कि नयी दिल्ली यूक्रेन से संबंधित घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रख रही है।

तिरुमूर्ति ने कहा, "भारत का हित एक ऐसा समाधान खोजने में है जो सभी देशों के वैध सुरक्षा हितों को ध्यान में रखते हुए तनाव को तत्काल कम कर सके और इसका उद्देश्य क्षेत्र तथा उसके बाहर दीर्घकालिक शांति और स्थिरता हासिल करना हो।"

तिरुमूर्ति ने कहा कि यूक्रेन के सीमावर्ती इलाकों समेत उस देश के विभिन्न हिस्सों में 20,000 से अधिक भारतीय छात्र और नागरिक पढ़ते एवं रहते हैं। उन्होंने कहा, "भारतीय नागरिकों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है।"

जापानी कैबिनेट ने यूनेस्को विरासत के लिए विवादास्पद खदान की नीलामी को मंजूरी दी

टोक्यो। जापानी कैबिनेट ने मंगलवार को युद्ध के समय के लिए श्रम से जुड़ी एक पूर्व सोने की खदान को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल करने के लिए नीलामी की मंजूरी दे दी। एक स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के हवाले से यह जानकारी मिली है।



योनहाप न्यूज एजेंसी ने क्योको न्यूज की रिपोर्ट के हवाले से कहा कि कूटनीतिक रूप से विवादास्पद बोली को कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई। टोक्यो बाद में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर को अनुशंसा पत्र देने की योजना बना रहा है।

27 जनवरी को, जापानी प्रधान मंत्री फुमियो किशिदा ने दक्षिण कोरिया के कड़े विरोध के बावजूद 2023 यूनेस्को विरासत सूची के लिए साढ़े द्वापार खदान को नामित करने की योजना की घोषणा की।

दक्षिण कोरियाई सरकार ने तुरंत इस फैसले पर कड़ा बंद्य व्यक्त किया और सियोल में अपने राजदूत कोइची आइबोशी को विरोध दर्ज करने के लिए बुलाया।

निगाटा प्रान्त में साढ़े द्वापार खदान में एक हजार से अधिक कोरियाई लोगों को कड़ी मेहनत के लिए मजबूर किया गया था। इस कदम से साझा इतिहास को लेकर सियोल और टोक्यो के बीच राजनयिक दरारें और गहरी हो सकती हैं।

कनाडा के पीएम हुए कोरोना पॉजिटिव

ओटावा। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन टर्डो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं देश में महामारी के मद्देनजर लगाए गए स्वास्थ्य प्रतिबंधों के खिलाफ व्यापक विरोध देखा जा रहा है।



सोमवार को ट्विटर पर उन्होंने कहा, आज सुबह, मैंने कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया। मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ और मैं इस सप्ताह सार्वजनिक स्वास्थ्य दिशानिर्देशों का पालन करते हुए दूर से काम करना जारी रखूँगा। हर कोई, कृपया टीका लगवाएं।

पीएम ने बताया की उनके तीन बच्चों में से दो पॉजिटिव पाए गए हैं।

वह और उसका परिवार कोविड-19 जोखिम की घोषणा के बाद से कई दिनों से आइसोलेट हैं, जिसका उन्होंने विवरण नहीं दिया है।

26 जनवरी को, टर्डो ने अपने मंत्रिमंडल के कई सदस्यों के साथ व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की।

सीएनएन की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि टर्डो परिवार को एहतियात के तौर पर एक अज्ञात स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया है क्योंकि ओटावा में कोविड-19 स्वास्थ्य प्रतिबंधों का विरोध जारी है।

अमेरिकी संसद ने कोविड-19 संकट से निपटने के वैश्विक प्रयासों के लिए भारत की सराहना की

वाशिंगटन। अमेरिकी संसद के 'ब्लैक कॉकस' ने कोविड-19 संकट से निपटने के वैश्विक प्रयासों में मदद करने और कम से कम 38 देशों को 80 लाख से अधिक टीके देने के लिए भारत की सराहना की।

प्रभावशाली ब्लैक कॉकस की अध्यक्ष जॉयसे बीटी ने अमेरिका में भारत के राजदूत तरणजीत सिंह संधू को लिखे एक पत्र में कहा, "मैं आपकी सरकार के प्रयासों की प्रशंसा करती हूँ क्योंकि उसने कम से कम 38 देशों को 80 लाख से अधिक टीके निस्वार्थ भाव से भेजे।" अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी ब्लैक कॉकस की सदस्य हैं।



ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने शोध को बढ़ाने की योजना की घोषणा की



कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने मंगलवार को 2.2 अरब डॉलर (1.5 अरब डॉलर) की शोध व्यावसायिकरण योजना का अनावरण किया।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, पैकेज में ऑस्ट्रेलिया के आर्थिक त्वरक के लिए 1.6 अरब डॉलर शामिल है, जो रक्षा, अंतरिक्ष, संसाधन प्रौद्योगिकी, खाद्य और पेय, स्वच्छ ऊर्जा और चिकित्सा उत्पादों के क्षेत्र में उच्च-संभावित अनुसंधान परियोजनाओं को फंड देगा।

उद्योग-केंद्रित पीएचडी में एक और 2.96 करोड़ डॉलर का निवेश किया जाएगा।

राष्ट्रीय विज्ञान एजेंसी कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंस्ट्रुमेंटल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन (सीएसआईआरओ) द्वारा प्रशासित इनोवेशन फंड को 1.5 करोड़ डॉलर तक बढ़ाया जाएगा।

मॉरिसन ने कहा कि फंडिंग का इंजेक्शन ऑस्ट्रेलियाई अनुसंधान को व्यावसायिक रूप से अधिक प्रतियोगी बना देगा।

उन्होंने कहा, यह ऑस्ट्रेलियाई नवप्रवर्तकों को उनकी परियोजना के प्रत्येक चरण के लिए फंड के अवसरों तक पहुंचने की अनुमति देगा, बशर्ते वे परियोजना की व्यवहार्यता और महत्वपूर्ण रूप से व्यावसायिक क्षमता को साबित करना जारी रख सकें।

हमें ऑस्ट्रेलियाई उद्योग और विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के बीच संबंधों के निर्माण में तेजी लाने की जरूरत है। हमें यहां ऑस्ट्रेलिया में अनुसंधान उद्यमियों की एक नई नस्ल विकसित करने की आवश्यकता है ताकि वे नए उत्पादों और नई कंपनियों और सबसे महत्वपूर्ण, नई नौकरियों को निर्माण कर सकें।

अमेरिका में जनवरी में 35 लाख से ज्यादा बच्चे कोरोना पॉजिटिव हुए

वाशिंगटन। अमेरिका में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच, जनवरी में 35 लाख से ज्यादा बच्चों में कोरोना



के मामले दर्ज किए गए।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स (एएपी) और चिल्ड्रन्स हॉस्पिटल एसोसिएशन (सीएचए) को जारी रिपोर्ट में कहा गया कि देश में 2020 में महामारी की शुरुआत के बाद से 1.14 करोड़ से ज्यादा बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए।

इनमें से लगभग 20 लाख मामले पिछले दो सप्ताह में जोड़े गए हैं।

एएपी ने कहा, 27 जनवरी को समाप्त सप्ताह के लिए देश में 808,000 से ज्यादा बच्चों में कोरोना के मामले दर्ज किए गए। इस सप्ताह बच्चों के कई मामले जोड़े गए, जिसने 2021 में डेल्टा वृद्धि के चरम स्तर को तिरगुना कर दिया।

यह लगातार 25वें सप्ताह में अमेरिका में बच्चों के कोरोना मामले 100,000 से ऊपर दर्ज किए गए।

एएपी के अनुसार, सितंबर 2021 के पहले सप्ताह से, लगभग 64 लाख बच्चों के मामले सामने आए हैं।

रूस ने यूक्रेन संकट कम करने के अमेरिकी प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया दी



संयुक्त राष्ट्र। रूस की सरकार ने यूक्रेन संकट को कम करने के उद्देश्य से अमेरिका के प्रस्ताव पर लिखित प्रतिक्रिया भेजी है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन के प्रशासन के तीन अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने गोपनीयता की शर्त पर यह जानकारी दी। रूस की यह प्रतिक्रिया तब आयी है, जब बाइडन प्रशासन क्रेमलिन पर यूक्रेन सीमा पर तनाव कम करने का दबाव बना रहा है। रूस ने यूक्रेन सीमा पर करीब 1,00,000 सैनिकों को तैनात किया है।

विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने रूस की प्रतिक्रिया की विस्तृत जानकारी देने से इनकार करते हुए कहा, "बातचीत को सार्वजनिक रूप से उजागर करना उचित नहीं होगा" और वे इसका फैसला रूस पर छोड़ते हैं कि वह अपनी प्रतिक्रिया को लोगों से साझा

करें या नहीं। इस बीच, रूस ने पश्चिम देशों पर यूक्रेन को लेकर "तनाव बढ़ाने" का मंगलवार को आरोप लगाया और कहा कि अमेरिका कीव में "नाजियों" को सत्ता में लेकर आया।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में मास्को ने यह टिप्पणी की, जब रूस और अमेरिका के प्रतिनिधियों के बीच तीखी बहस हुई।

अमेरिका की राजदूत लिन थॉमस ग्रोनफील्ड ने पलटवार करते हुए कहा कि रूस यूक्रेन सीमा पर 1,00,000 से अधिक सैनिकों को तैनात कर रहा है जो दशकों में यूरोप में "सबसे बड़ा सैन्य जमावड़ा" है।

रूसी राजदूत वैसिली नेवेंजिया ने बाइडन प्रशासन पर "तनाव को बढ़ाने और उकसाने" का आरोप लगाया।

तुर्की का पर्यटन राजस्व 2021 में दोगुना हुआ

अंकारा। तुर्की के पर्यटन राजस्व में 2021 में सालाना आधार पर 103 फीसदी की बढ़ोतरी हुई और असफलताओं के बावजूद यह 24.48 अरब डॉलर तक पहुंच गया। ये जानकारी देश के सांख्यिकी संस्थान ने दी।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले साल की चौथी तिमाही में देश की पर्यटन आय में 95 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 7.63 अरब डॉलर की वृद्धि दर्ज की गई।

इसमें कहा गया कि व्यक्तिगत व्यय ने 2021 में 19.68 अरब डॉलर की आय का गठन किया, जबकि पैकेज टूर व्यय ने 4.8 अरब डॉलर कमाए।

बीते साल कोरोना महामारी से संबंधित प्रतिबंधों से तुर्की का पर्यटन बुरी तरह प्रभावित हुआ था, खासकर जब रूस ने देश में बढ़ते दैनिक मामलों के कारण तुर्की के लिए सभी उड़ानों को लगभग तीन महीने के लिए रोक दिया था।



तुर्की के तटीय क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से भूमध्यसागरीय प्रांत अंताल्या के लिए रूसी बाजार काफी महत्वपूर्ण था।

जुलाई और अगस्त 2021 में, कई बड़े पैमाने पर जंगल की आग ने एजियन और तुर्की के भूमध्यसागरीय तटों के साथ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों को चपेट में ले लिया, जिससे

पर्यटन राजस्व भी कम हो गया, और कई यात्रियों को अपनी योजनाओं को रद्द करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

पिछले साल, देश तुर्की लीरा के मूल्यहास के खिलाफ भी संघर्ष कर रहा था, जिसने डॉलर के मूल्य का 44 प्रतिशत खो दिया था।

इस बीच, कोरोना के खिलाफ देश के टीकाकरण के प्रयास पूरी गति से जारी हैं और अब तक 1.41 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन खुराक दी जा चुकी हैं।

स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी नए आंकड़ों के अनुसार, सोमवार तक 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के डबल डोज वाले लोगों की दर 84.38 प्रतिशत थी।

साल 2019 में 4.5 करोड़ पर्यटकों संख्या के बाद तुर्की ने कुल 34.5 अरब डॉलर का राजस्व अर्जित किया, लेकिन महामारी के कारण 2020 में इसे 70 प्रतिशत से ज्यादा का नुकसान हुआ।

म्यांमा में सेना के सत्ता में आने के बाद से हिंसा बढ़ गई है: संरा दूत

संयुक्त राष्ट्र। म्यांमा के लिए संयुक्त राष्ट्र की नई विशेष दूत नोलीन हेजर ने सोमवार को दावा किया कि सेना के सत्ता में आने के बाद से हिंसा और क्रूरता बढ़ गई है, जिसके विरोध में देश में एक आंदोलन छिड़ गया है।

उन्होंने कहा कि सभी पक्षों ने "हिंसा को समाधान के रूप में इस्तेमाल करने" को लेकर रख रख कर लिया है। हेजर ने न्यूरॉक में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन में कहा कि म्यांमा की स्थिति तेजी से अस्थिर हो गई है और हवाई हमलों सहित सैन्य अभियानों से नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि पिछले एक



साल में लगभग 1,500 नागरिक मारे गए हैं और विस्थापित लोगों की संख्या 2021 के अंत के 3,20,000 के आंकड़े से बढ़कर अब 4,00,000 से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा, "यह एक

वाली हेजर ने कहा कि म्यांमा की लगभग आधी आबादी अब गरीबी के दलदल में है और 1.44 करोड़ से ज्यादा लोगों को मानवीय सहायता और सुरक्षा की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आसियान के विदेश मंत्री और कुछ नेता पिछले अप्रैल में हुई बैठक में पांच सूत्रीय सहमति को लागू करने के लिए म्यांमा पर दबाव डाल रहे हैं, जिसमें म्यांमा सेना के कमांडर सीनियर जनरल मिन आंग हेइंग भी शामिल हैं।

गौरतलब है कि हेइंग ने एक फरवरी 2021 की सुबह सू ची और उनकी सरकार तथा सत्तारूढ़ 'नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी' के शीर्ष सदस्यों को गिरफ्तार करके सत्ता पर कब्जा कर लिया था।

बजट ने मायूस किया, आम लोगों के लिए कुछ भी नहीं : केजरीवाल

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कहा कि वर्ष 2022-23 के बजट ने लोगों को मायूस किया है क्योंकि इसमें आम जनता के लिए कुछ भी नहीं है।

उन्होंने ट्वीट किया, "क्रोना काल में लोगों को बजट से बहुत उम्मीद थी। बजट ने लोगों को मायूस किया। आम जनता के लिए बजट में कुछ भी नहीं है। महंगाई कम करने के लिए कुछ नहीं है।"

उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया।

दिल्ली दंगों के दौरान हत्या के मामले में हाईकोर्ट ने 2 लोगों को दी जमानत

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में फरवरी 2020 में हुए दंगों के दौरान एक युद्ध महिला की हत्या के मामले में गिरफ्तार दो लोगों को जमानत दे दी।

न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने अरुण कुमार और रवि कुमार को जमानत दे दी, जबकि उनके सह-आरोपी विशाल सिंह को जमानत देने से इनकार कर दिया गया।

302-हत्या के लिए सजा, 307-हत्या का प्रयास, 396-हत्या के साथ छेकती, 148-दंगा, घातक हथियार से लैस, 149-गैरकानूनी सभा, 436- आग या विस्फोटक पदार्थ के इरादे से शरात मकान नष्ट करना तथा धारा 147- दंगा करने पर दण्ड के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस के अनुसार, उत्तर-पूर्वी दिल्ली के भजनपुरा इलाके के गमरी रोड पर अपने परिवार के साथ रहने वाली 85 वर्षीय अकबरी बेगम की 25 फरवरी, 2020 को भीड़ द्वारा हमला किए जाने और उनके घर में आग लगाने के कारण दम घुटने से मौत हो गई थी।

पुलिस के अनुसार, सईद सलमानों, उनके बेटे द्वारा दर्ज की गई शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी, उन्होंने कहा जब परिवार के अन्य सदस्य छत पर चढ़ गए, तो बुजुर्ग महिला नहीं जा सकी और दम घुटने से उनकी मौत हो गई। दमकल कर्मियों द्वारा आग पर काबू पाने के बाद उनका शव घर की दूसरी मंजिल से बरामद किया गया। पुलिस ने कहा, शव एक तह बिस्तर पर पड़ा मिला था।

एनडीएमसी उपाध्यक्ष ने बजट को बताया सकारात्मक

नई दिल्ली। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने केन्द्रीय बजट को सकारात्मक बताया है। उन्होंने जनता के हित में बजट पेश करने के लिए प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को बधाई दी है। बजट पर अपनी प्रतिक्रिया में उन्होंने कहा कि कोविड महामारी की लहर के बावजूद बजट के आंकड़े प्रशंसनीय हैं और भारत के नागरिकों के हित में हैं। हमारे टीकाकरण अभियान की गति और कवरेज ने महामारी से निपटने में बहुत मदद की है। टीकाकरण कार्यक्रम का तेजी से कार्यान्वयन स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे की मजबूती को दर्शाता है।

तीन गर्लफ्रेंड पर खर्च के लिए लूटपाट करने वाला दबोचा

नई दिल्ली। करोड़ बाग थाना पुलिस ने तीन गर्लफ्रेंड पर खर्च करने के लिए लूटपाट की वारदात को अंजाम देने वाले एक बदमाश को उसके साथी के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में 24 वर्षीय सुल्तान और उसका साथी 23 वर्षीय नवीन शामिल हैं। इन पर लूटपाट, झपटमारी, बाहन चोरी के आधा दर्जन मामलों में शामिल होने का आरोप है। आरोपियों से चोरी की स्कूटी समेत दो स्कूटी बरामद हुई हैं। डीसीपी श्वेता चौहान ने बताया कि सूचना मिली थी कि करोड़ बाग मेट्रो स्टेशन के पास कुछ बदमाश वारदात को अंजाम देने आने वाले हैं। काले रंग की स्कूटी पर सवार दो सदियों को रोकने पर उन्होंने भागने का प्रयास किया। पुलिस टीम ने पीछा कर दोनों को पकड़ लिया। आरोपियों की पहचान सुल्तान और नवीन के रूप में हुई। आरोपी सुल्तान ने बताया कि पिता स्थानीय एमएलए के दफ्तर में काम करते हैं। सुल्तान स्थानीय नेताओं से जान-पहचान का फायदा उठाता है। उसकी तीन गर्लफ्रेंड हैं, जिन्हें डिस्को व बार ले जाने के लिए वह लूटपाट करता है। वहीं, नवीन ने बताया कि माता-पिता की मौत हो चुकी है। उसकी एक गर्लफ्रेंड है, जिससे वह शादी करने वाला है। इसके लिए लूटपाट करके रुपये जुटा रहा है।

साप्ताहिक बाजारों की तुलना नियमित दुकानों से नहीं की जा सकती : उच्च न्यायालय

नई दिल्ली। उच्च न्यायालय ने कहा है कि साप्ताहिक बाजारों में रेहड़ी-पट्टी लगाने वाले कारोबारी आवश्यक सेवाएं और वस्तुओं को बेचते हैं, बावजूद इसके उनकी तुलना नियमित दुकानों / प्रतिष्ठानों से नहीं की जा सकती है। न्यायालय ने आवश्यक वस्तुओं और सेवाएं मुहैया कराने वाले नियमित दुकानों / प्रतिष्ठानों की तर्ज पर महामारी में साप्ताहिक बाजारों को खोलने की अनुमति देने की मांग को ठुकराते हुए यह टिप्पणी की है।

केंद्रीय बजट पर कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रेन्स फाउंडेशन की प्रतिक्रिया

नई दिल्ली। कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रेन्स फाउंडेशन (केएससीएफ) ने केंद्र सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में बच्चों से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के मद में कटौती करने पर चिंता ज़ाहिर की है। पिछले बजट में बच्चों के मद में कुल बजट का 2.46 फीसदी धन आवंटित किया गया था। जबकि वित्त वर्ष 2022-23 में यह घटकर 2.35 फीसदी रह गया है। यह सन 2008 से बाल अधिकारों के मद में आवंटित की जा रही अंभी तक की सबसे कम धनराशि है।

कोरोना महामारी ने बच्चों की शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य से लेकर उनकी देखभाल, पोषण, पेनजल, स्वच्छता और संरक्षण को काफी प्रभावित किया है। समाज के हाशिए

पर रहने वाले गरीब लोगों की आमदनी में कमी होने से उनके बच्चों को बाल श्रम, ट्रेफिकिंग, शोषण, यौन दुर्व्यवहार, अपमान और अन्याय का सामना करना पड़ रहा है। इन सभी पहलुओं को देखते हुए केंद्रीय बजट में बच्चों के हित में धनराशि बढ़ाए जाने की जरूरत थी। कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रेन्स फाउंडेशन महिला और बाल विकास मंत्रालय के बजट आवंटन पर भी चिंता ज़ाहिर करता है, जिसमें पिछले वित्तीय साल के मुकाबले 8 प्रतिशत की कमी की गई है। जो वर्ष 2020-21 के 20,401 करोड़ रुपये से घटकर 2022-23 में 18,859 करोड़ रुपये हो गया है।

पिछले चार वर्षों के आंकड़ों का विश्लेषण भी राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) के

केजरीवाल ने सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता के लिये 10 लाख रुपये की सहायता की घोषणा की

नई दिल्ली। शाहदरा जिले के कस्तूरबा नगर में 20 साल की युवती के साथ हुई हैवानियत मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को पीड़िता को 10 लाख की सहायता राशि देने का एलान किया है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि "मैंने इस बेटी को मदद के लिए 10 लाख सहायता राशि देने का निर्णय किया है। दिल्ली सरकार इस बेटी को न्याय दिलवाने के लिए हर संभव कोशिश करेगी। हम उसके लिए अच्छा वकील नियुक्त कर रहे हैं साथ ही उक्त मामले को फास्ट ट्रैक भी करेगी ताकि जल्द से जल्द बेटी को न्याय मिल सके।"

उल्लेखनीय है कि उक्त घटना में

झूठ और अफवाह फैलाने के मामले में पुलिस ने सोमवार को जांच के बाद दो टिवटर हैंडल व एक यू-ट्यूबर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दोनों टिवटर हैंडल के जरिये आरोपितों ने पीड़िता के 'आत्महत्या' करने और घटना को सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास किया। वहीं मोजो नाम से यू-ट्यूबर चलाने वाले मदनलाल नामक शख्स पर पीड़िता और उसके परिवार की पहचान उजागर करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। डीसीपी आर.सत्यसुंदरम ने बताया कि पुलिस जल्द ही इनको बुलाकर इनसे पूछताछ करेगी। तीनों ही मामले विवेक विहार थाने में दर्ज किए गए हैं।



डीसीपी के अनुसार, पहला मामला sukhpreet slatch

दक्षिणी निगम ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 से संबंधित स्वच्छता व जागरूकता अभियान तेज किये

नई दिल्ली। दक्षिणी निगम ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के मद्देनजर सभी जों में विशेष स्वच्छता व जागरूकता अभियान तेज कर दिया है। सभी जों में इन अभियानों के द्वारा विशेष रूप से कूड़े के पृथक्करण, सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध और गीले कूड़े की कम्पोस्टिंग पर बल दिया जा रहा है।

पश्चिमी जों में आज जनकपुरी की सी ब्लॉक मार्केट व खुबीर नगर में गीले व सूखे कूड़े को अलग-अलग करने हेतु जनजागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। नागरिकों को प्रेरित किया गया कि वे अपने घर पर ही गीले और सूखे कूड़े को अलग-अलग करें।

दक्षिणी निगम ने वाए वेस्ट वेड-सडेस फाउंडेशन और ब्राइट प्वाइंस फाउंडेशन के साथ मिलकर रिस्कर द्वारा गीला और सूखा कचरा अलग करने का संदेश दिया। इसके साथ इसमें प्लास्टिक की थैलियों को त्याग कर कपड़े के थैले को अपनाने का भी संदेश है। वेस्टवेस्ट दक्षिणी जों के 60000 बच्चों की

किताबों में लगाने के लिये भेजे जायेंगे। रिस्कर में हिंदी, अंग्रेजी के साथ-साथ तस्वीरों के माध्यम से ये संदेश लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया गया है। इस कार्यक्रम में दक्षिणी जों की उपयुक्त डॉ अकिता चक्रवर्ती व निगम पार्षद, डा नन्दनी शर्मा उपस्थित थे। इसके अतिरिक्त दक्षिणी जों में प्लास्टिक लाओ खाद ले जाओ- पहल के तहत जी के 1 स्थित अर्चना नर्सरी को जैविक खाद भी वितरित की गयी।

मध्य जों में भी स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय कार्यालय की दीवारों पर स्वच्छता से संबंधित सुन्दर व आकर्षक वॉल पेंटिंग बनाई गयी। इस सौन्दर्यीकरण कार्य से निश्चित रूप से नागरिक स्वच्छता के प्रति जागरूक होंगे और स्वच्छ सर्वेक्षण में अपना सहयोग देंगे। मध्य जों के त्रिकोण पार्क में सफाई सैनिकों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें उन्हें स्वच्छता, कूड़े के पृथक्करण, स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर शिक्षित किया गया।

'बच्ची को इंसाफ' की मांग को लेकर नेशनल अकाली दल ने किया प्रदर्शन

कस्तूरबा नगर जैसी घटना कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे : पम्मा

नई दिल्ली। दिल्लीके कस्तूरबा नगर शाहदरा में शर्मनाक घटना घटी इसके विरोध में नेशनल अकाली दल की ओर से वेस्ट दिल्लीके सुभाष नगर चौक पर दल की कल्चर विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष रश्मीत कौर बिन्दा की अध्यक्षता में वरोध प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर परमजीत सिंह पम्मा व रश्मीत कौर बिन्दा ने कहा कि ऐसी घटना कभी भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिले। इस घटना ने पूरे देश का दिल झकझोर दिया है बड़े दुख की बात है इतनी देर तक यह घटना होती रही और प्रशासन सोया रहा। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद



प्रशासन की आंखें खुली।

इस अवसर पर दिल्ली प्रदेश के

में इस प्रकार की घटना हो जाती है तो पूरे देश में कहां पर बच्चियां सुरक्षित है।

इस अवसर पर समाजसेविका अंजू शर्मा ने कहा गृह मंत्री को हस्तक्षेप करके जल्द से जल्द दोषियों को सजा दिलानी चाहिए। क्योंकि ऐसी घटना से पूरे देश की छवि खराब होती है।

इस अवसर पर इंद्रजीत सिंह आष्ट,परिवंदर सिंह सभरवाल, जसविंदर सिंह सभरवाल, तरलोचन सिंह, हैपपी सिंह, कन्हैयालाल,रामप्यारी,गीता, बलविंदर और कुलजिंदर कौर ने भी कड़वी निंदा की। बच्ची को इंसाफ दो और दोषियों को सजा दो जैसे नारे लगाए गए।

मोदी सरकार की एएमआरयूटी योजना से पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने किया झील का कायाकल्प

नई दिल्ली। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने आज कहा कि जिस तरह से भाजपा शासित नगर निगम ने दिल्ली में विकास कार्य किए हैं, वह जमीन पर दिख रहा है। आज मोदी सरकार की अमृत (एएमआरयूटी) योजना के अंतर्गत पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा निर्मित वेलकम झील के पुनर्विनीकरण मौके पर श्री गुप्ता ने कहा कि इस झील से पर्यावरण संरक्षण-संवर्धन व पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही साथ क्षेत्र के सौंदर्यीकरण में लाभ होगा। इसके साथ ही इस झील को अल्ट झील एवं उपवन के नाम से जाना



जाएगा। आज का यह कार्यक्रम दिल्ली सरकार को आइना दिखाने वाला है।

आदेश गुप्ता ने कहा कि निगम लगातार दिल्ली की जनता के लिए काम कर रहा है और दिल्ली के सौंदर्यीकरण का विशेष ध्यान रखा

जा रहा है। निगम द्वारा बनाया गया भारत दर्शन पार्क इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। भारत के अलग-अलग राज्यों की 21 प्रतिमाएं चाहे वह मंदिर हो या फिर ऐतिहासिक महल, का समायोजन भारत दर्शन पार्क में किया गया है। उन्होंने वेलकम झील

नवीनीकरण को ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि कूड़े के ढेर को हटकर एक सुंदर और साफ झील का निर्माण करना जिसमें स्वच्छ जल का बहाव हो रहा है अपने आप में एक अद्भुत कार्य है। कार्यक्रम में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद मनोज तिवारी, प्रदेश महामंत्री हर्ष मल्होत्रा, पूर्वी दिल्ली नगर निगम महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल, विधायक जितेंद्र महजन, जॉन चैयरमैन प्रवेश शर्मा, स्थायी समिति के अध्यक्ष वीर सिंह पंवार, जिला अध्यक्ष मास्टर विनोद एवं मोहन गोयल, निगम पार्षद अजय शर्मा सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।

आम जनता पर बोझ कम करने वाला बजट : बिधूड़ी

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने बजट को प्रगतिशील, दूरदर्शी और आम जनता का बोझ कम करने वाला बजट बताया है। उन्होंने कहा कि बजट में हर तबके का और खासतौर पर गरीब वर्ग पर खास ध्यान दिया गया है। 80 लाख नए घर बनाने की घोषणा से गरीबों का अपने घर का सपना साकार होगा। इसके अलावा 25 हजार किमी. लंबे हाईवेज देश की तरक्की का नया अध्याय लिखने वाले हैं। बजट में इलेक्ट्रॉनिक सामान, मोबाइल चार्जर, कैमरा, बटन, जिपर, चमड़ा, पैकेजिंग बॉक्स और कई चीजें सस्ती होने वाली हैं। बिधूड़ी ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था जिस तरह कोरोना के बाद भी जबरदस्त तरक्की कर रही है, वह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता का ही प्रतीक है। पिछले महीने के दौरान जीएसटी की रिकॉर्ड वसूली उसी का एक प्रमाण है और वित्त मंत्री ने इस बजट से उसी दूरदर्शिता का परिचय दिया है।



मोदी सरकार का यूनिथन बजट दिल्लीवासियों के लिए जीरो बजट रहा- चौ. अनिल कुमार

नई दिल्ली। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौ. अनिल कुमार ने कहा कि भाजपा की मोदी सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए पेश किए गए यूनिथन बजट में दिल्ली के लिए कुछ नहीं दिया है। 2022-23 का बजट पूरी तरह से जीरो बजट है जिसमें असमान छूटी महंगाई और

कोविड संक्रमण के कारण आर्थिक मंदी झेल रही राजधानी के लोगों को कोई राहत नहीं दी है। पेट्रोल-डीजल सहित रसोई गैस की बढ़ती दरों में कमी और पेट्रोल और डीजल पर एकसाइन ड्यूटी में राहत की उम्मीद कर रहे दिल्लीवासियों, बजट के बाद खाली हाथ रह गए हैं। भाजपा की

केन्द्र सरकार के 7 वर्षों के शासन में महंगाई और बेरोजगारी ने कीर्तिमान स्थापित किए हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मोदी सरकार ने बजट में अपने पूंजीपति मित्रों के हित साधने का काम किया है जबकि गरीबों और नौकरीपेशा लोगों को राहत देने को पूरी तरह रहखा गया है।

रोज़गार देना न सरकार की नीयत में, न नीति में: अनुपम

युवाओं के लिए आम बजट दुर्भाग्यपूर्ण: अनुपम

नई दिल्ली। बजट में राष्ट्रीय आपदा बन चुकी बेरोजगारी को लेकर हुए अनदेखी पर युवा नेता अनुपम ने मोदी सरकार पर कठारा प्रहार किया है। बेरोजगारी के मुद्दे को राष्ट्रीय बहस में लाने वाले युवा हल्ला बोल संस्थापक अनुपम ने कहा कि जब सरकार की नीयत ही नहीं है तो भला नीति कैसे होगी। रोजगार देना सरकार की नीति में इसलिए नहीं है क्योंकि ये लोग बेरोजगारों की एक ऐसी फौज बनाना चाहते हैं जो जाति धर्म में अंधे होकर इनकी राजनीति का चारा बन सके, रैलियों की भीड़ बन सके। तभी तो बजट में नौकरियों को लेकर कुछ भी ठोस नहीं है, वो भी तब जब बेरोजगारी राष्ट्रीय आपदा का रूप ले चुकी है और देश में आंदोलन चल रहा। अनुपम ने कहा कि सरकार यदि थोड़ी भी गंभीर होती तो कम से कम यह स्वीकारती कि बेरोजगारी आज एक भीषण संकट है। लेकिन समाधान निकालने के उपाय करना तो दूर की बात, मोदी सरकार समस्या को स्वीकार करने की तैयार नहीं। शहरी रोजगार कानून जैसी कोई बात करना तो दूर, कोरोना में ढल का



अनुपम

काम करने वाले मनोरोग के बजट को भी कम कर दिया गया। मॉडल एजाम कोडकी हमारी मांग पर भी सरकार का ध्यान नहीं दिखा जिससे लाखों रिक्त सरकारी पदों को समयबद्ध ढंग से भरा जा सकता था। वित्त मंत्री जी ने आत्मनिर्भर योजना और मेक इन इंडिया के नाम पर रोजगार की कुछ घोषणाएँ तो की लेकिन बिना ठोस कार्ययोजना के इनका मतलब नहीं। अनुपम ने मोदी सरकार के आम बजट को युवाओं के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि यदि सरकार का ऐसा ही रवैया रहा तो रोजगार के लिए देश में बड़ा आंदोलन होगा।

प्रो. भुल्लर की रिहाई के संबंध में केजरीवाल सभी पंजाबियों की मांग को पूरा करें: जगदीप सिंह काहलौं

नई दिल्ली। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष स. हरमीत सिंह कालका ने कहा है कि अगर केजरीवाल सरकार ने प्रो. दिवंद्रपाल सिंह भुल्लर की रिहाई के तुरंत आदेश नहीं दिए तो दिल्ली कमेटी द्वारा उनके आवास का घेराव किया जाएगा। आज यहां एक प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए स. हरमीत सिंह कालका ने यह चेतावनी दी। उनके साथ कमेटी महासचिव स. जगदीप सिंह काहलौं व अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। स. कालका ने कहा कि बहुत ही हैरान करने वाली बात है कि अरविंद केजरीवाल के अपने गृह मंत्री सत्येंद्र जैन की अगुवाई वाले सजा समीक्षा बोर्ड ने प्रो. भुल्लर की रिहाई के लिए एक रद्द कर दिया है जबकि केजरीवाल यह कह रहे हैं कि उनका रिहाई की प्रक्रिया से कोई सरकार नहीं है और ना ही उन्हें इसकी कोई जानकारी है। मीडिया

को सजा समीक्षा बोर्ड की मीटिंग की कार्रवाई के विवरण जारी करते हुए स. कालका ने कहा कि इस बोर्ड में 7 में से 5 सदस्य श्री केजरीवाल की अगुवाई वाली सरकार से सीधे तौर पर संबंधित हैं और अभी तक केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर केजरीवाल सरकार ने तुरंत प्रो. भुल्लर की रिहाई के आदेश नहीं दिए तो हम उनके आवास का घेराव करेंगे। स. कालका ने केजरीवाल को भाई इकबाल सिंह (फ्रांस वाले) से किया वायदा भी याद दिलाया जब उन्होंने कहा था कि प्रो. भुल्लर की रिहाई जल्द होगी। उन्होंने इस मामले पर केजरीवाल को चिढ़ी भी लिखी है और मिलने का समय भी मांगा है पर केजरीवाल मिलने का समय नहीं दे रहे अपर उनका रवैया यही रहा तो हम उनके आवास का घेराव करेंगे।

आम बजट वर्ष 2022-23: दिल्ली पुलिस की बेहतरी के लिए 1701 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस को अत्याधुनिक बनाने के लिए इस बार के बजट में उसे 1701 करोड़ रुपए बीते वर्ष के मुकाबले ज्यादा मिले हैं। दिल्ली पुलिस को 2021-22 के बजट में जहां 8654.26 करोड़ रुपये की राशि मिली थी तो वहीं वर्ष 2022-23 के बजट में उन्हें 10355.29 करोड़ रुपए मिले हैं। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि इससे दिल्ली पुलिस को मजबूत बनाने में काफी मदद मिलेगी। पुलिस मुख्यालय से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2022-

23 के बजट में इस्टैब्लिशमेंट से संबंधित खर्च के लिए दिल्ली पुलिस को 9808 करोड़ रुपए दिए गए हैं। वहीं 287 करोड़ रुपए दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए बजट में दिए गए हैं। इस राशि से सीसीटीवी के अलावा विभिन्न अत्याधुनिक उपकरण खरीदे जाएंगे जिससे कानून व्यवस्था और कम्प्यूटेशन सिस्टम जैसे साइबर हार्डवेयर और डिजिटल ट्रेकिंग रॉडियो सिस्टम को बढ़ावा मिलेगा। इंटेलिजेंट ट्रेफिक

मैनजमेंट सिस्टम सहित कुछ योजनाओं पर भी यह राशि खर्च की जा सकेगी। इसके अलावा 259 करोड़ रुपए पुलिस को इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर मजबूत बनाने के लिए दिए गए हैं। इस राशि से ऑफिस की बिल्डिंग, रिहायशी बिल्डिंग, नए पुलिस हेड क्वार्टर के रखरखाव का काम किया जाएगा। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस के लिए नए घर बनाने पर यह राशि खर्च की जाएगी ताकि पुलिसकर्मियों के आवास की समस्या का समाधान हो सके।

भाजपा को दिया अपनों ने झटका

रमेश सराफ धर्मोरा

पार्टी विद डिफरेंस की टैग लाइन के साथ राजनीति में खुद को अन्य सभी पार्टियों से अलग व श्रेष्ठ बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) इन दिनों अपनों द्वारा दिए जा रहे झटकों से उबर नहीं पा रही है।

देश के पांच राज्यों उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। पांचों प्रदेशों में चुनाव लड़ने वाले सभी राजनीतिक दलों द्वारा अपने-अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की जा रही है। इसी दौरान विभिन्न पार्टियों के नेताओं द्वारा दलबदल का खेल भी जोरों से चल रहा है। इस दौरान सबसे अधिक झटका भाजपा को लगा है। कुछ वर्षों पूर्व सत्ता के लालच में भाजपा में शामिल होकर सत्ता का सुख भोगने वाले नेता एन चुनाव के वक्त भाजपा छोड़कर दूसरे दलों में शामिल होने लगे हैं।

भाजपा के बढ़ते जनाधार को देखकर दूसरे दलों के बहुत से ऐसे मौकापरस्त नेता जिनकी अपने दलों में दाल नहीं गल रही थी, वो सभी भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा ने भी दूसरे दलों से आने वाले नेताओं को भरपूर उपकृत किया। उन्हें विधानसभा व लोकसभा का चुनाव भी लड़वाया तथा चुनाव जीतने पर उनको मंत्री भी बनाया। ऐसे में दलबदल कर पार्टी में आने वाले नेताओं के क्षेत्रों में वर्षों से भाजपा के लिए काम



करने वाले पार्टी नेता खुद को उर्ध्वक्षित महसूस करने लगे। दल-बदलू नेताओं को भाजपा में पूरी तरजीह मिली। इसका फायदा उठाकर उन्होंने जहां आर्थिक रूप से मजबूती प्राप्त की, वहीं पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं को दरकिनारा कर अपने समर्थकों को विभिन्न पदों पर बैठाया। इससे पार्टी के मूल कार्यकर्ताओं में निराशा व्याप्त होने के कारण वह धीरे-धीरे मुख्याधार से किनारे हो गए।

लंबे समय तक सत्ता का दोहन करने के कारण अन्य दलों से भाजपा में आये बहुत से

नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे। उनके नाम के साथ कई तरह के विवाद जुड़ गए। ऐसे में चुनाव नजदीक आने पर जब उन्हें पार्टी में फिर से टिकट नहीं मिलने का अंदेश हो गया तो उन्होंने अपने पद पर रहते ही भाजपा विरोधी किसी अन्य पार्टी में शामिल हो गए। इससे एक तो चुनाव के वक्त पार्टी छोड़ने से जहां भाजपा की हवा खराब हुई। वहीं, पार्टी के सामने एकाएक मजबूत प्रत्याशी खड़ा करना मुश्किल हो गया। दूसरे दलों से भाजपा में आए कई नेताओं ने तो पद पर रहते ही भाजपा

को अलविदा कह कर पार्टी की किरकिरी भी कराई।

2014 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस से भाजपा में आए नाना पटोले ने भाजपा टिकट पर प्रफुल्ल पटेल जैसे दिग्गज नेता को पराजित किया था। मगर तीन साल बाद ही उन्होंने भाजपा व संसद से इस्तीफा देकर कांग्रेस की सदस्यता ले ली थी। नाना पटोले के इस्तीफा देने के बाद भंडारा गोंदिया लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मधुकर राव कुकड़े ने भाजपा प्रत्याशी हेमन्त श्रवण पटेल को हरा दिया था। उस उप चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को कांग्रेस का भी समर्थन प्राप्त था।

पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान दूसरी पार्टी से भाजपा में आए उत्तर प्रदेश में संसद उदित राज, उत्तर प्रदेश में बहराइच के सांसद रही सावित्रीबाई फुले, आजमगढ़ से पूर्व सांसद रामकांत यादव, हिमाचल प्रदेश के सुखराम जैसे कई बड़े नेताओं ने भाजपा छोड़कर दूसरे दलों का दामन थाम लिया था। जो कुछ वर्षों पूर्व ही दूसरी पार्टियों से भाजपा में आए थे।

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पूर्व मुकुल राय सहित बहुत से बड़े नेता भाजपा में शामिल हुए थे। सभी को बंगाल में भाजपा सरकार बनती दिख रही थी। इसलिए अपने लाभ के लिए भाजपा में आने वालों की बहुत बड़ी संख्या थी। मगर जैसे ही विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और ममता बनर्जी भारी बहुमत से तीसरी बार

मुख्यमंत्री बनीं। उसके बाद भाजपा में दूसरे दलों से आए दलबदलू नेताओं ने पार्टी को छोड़ना शुरू कर दिया। सबसे पहले भाजपा के बड़े नेता व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल राय ने ममता बनर्जी से फिर से हाथ मिला लिया। उसके बाद केंद्र में मंत्री रहे बाबुल सुप्रियो ने मंत्री पद से हटाने से नाराज होकर भाजपा व संसद सदस्यता से त्यागपत्र देकर तुणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। अब तक बंगाल में भाजपा के कई बड़े नेता व करीबन दस विधायक तुणमूल कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। इसी तरह 2017 में विधानसभा चुनाव के दौरान उत्तराखण्ड में कांग्रेस से भाजपा में आकर मंत्री बने यशपाल आर्य अपने विधायक बेटे संजीव आर्य के साथ व हरक सिंह रावत भाजपा छोड़कर फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए हैं।

उत्तर प्रदेश में भी स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी, दारा सिंह चौहान मंत्री पद से इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। उनके साथ ही करीबन 15 अन्य विधायकों ने भी भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। इनके अलावा टिकट नहीं मिलने पर कई अन्य नेताओं के भी भाजपा छोड़ने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि भाजपा ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे बड़े नेता के पार्टी छोड़ने पर उनके प्रतिद्वंद्वी रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री व कांग्रेस के बड़े नेता आरपीएन सिंह को भाजपा में शामिल कर लिया है। आरपीएन सिंह, स्वामी प्रसाद मौर्य के क्षेत्र पडरौना से ही पूर्व में तीन बार विधायक रह चुके

हैं। वह मौर्य की कुर्मी जाति से हैं तथा पडरौना उनका परंपरागत विधानसभा क्षेत्र रहा है।

पार्टी में चल रहे दलबदल के बारे में भाजपा के बड़े नेताओं का कहना है कि जिनके टिकट कटने की पूरी संभावना है, वहीं लोग पार्टी छोड़कर दूसरे दलों में जा रहे हैं। मगर भाजपा को भी अपने अंतर्मन में झंकाणा होगा कि एन चुनाव के वक्त पार्टी के नेता पार्टी छोड़कर क्यों जाते हैं। इसके जिम्मेवार कहीं न कहीं पार्टी के ही बड़े नेता हैं। जो सिर्फ सरकार बनाने के लिए बिना सोचे समझे दूसरे दलों के ऐसे नेताओं को पार्टी में शामिल कर लेते हैं जिनकी भाजपा के प्रति ना तो कभी निष्ठा रही है ना ही भाजपा की विचारधारा से उनका तालमेल रहा है।

पिछले सात वर्ष से अधिक समय से भाजपा की केंद्र में सरकार चल रही है। अधिकांश राज्यों में भी भाजपा व उनके सहयोगी दलों की सरकार है। ऐसे में भाजपा आलाकमान को सोचना चाहिए कि दूसरे दलों से आने वाले नेताओं को पार्टी में शामिल करने के बजाए अपनी ही पार्टी का संगठन मजबूत किया जाए। पार्टी में काम करने वाले कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाया जाए। वर्षों से सहयोगी रहे दलों की उपेक्षा करने की बजाय उनको पूरा सम्मान देना चाहिये। ताकि चुनाव के समय पार्टी को दलबदल का सामना नहीं करना पड़े। जिससे पार्टी इस प्रकार से शर्मिंदगी झेलने से बच सके।

सम्पादकीय

धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र को जातिगत आधार पर सुदृढ़ करने का सपना

डा. रवीन्द्र अरजरिया

चुनावी समीकरणों से गर्माती हवाओं के मध्य पर्यावरणीय स्थितियों की उदक निरंतर कम होती जा रही है। दिन के तापमान में बढ़ोतरी होते ही चुनानी जंग में सोशल मीडिया से लेकर व्यक्तिगत सम्पर्कों तक में तेजी आने लगी है। स्टार प्रचारकों को धरातल पर उतारने के साथ ही अतीत के पत्रों को पलटने का काम नित नई ऊंचाइयों खूने लगा है। भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह ने अपनी शतरंजी चालें चल कर बाजी जीतने का

क़दम रखा है वहीं केन्द्र और प्रदेश सरकारों के दुःखद अध्यायों को समाजवादी पार्टी पलटने लगी है। कांग्रेस के कुछ घोषित उम्मीदवारों ने तो चुनावी टिकट मिलने के बाद भी पार्टी को तिलांजलि दे दी है। चुनावी जंग में पंजे का परिवारवाद पर रेखांकित फार्मूला तो टिकट वितरण के दौरान ही ध्वस्त हो गया है। उत्तराखण्ड से लेकर पंजाब तक के उदाहरण चटखारे लेकर कहे-सुने जा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की धीमी गति को लेकर सभी दल सशकित हैं। आम आदमी पार्टी की ऐजेन्डा स्थान के साथ बदलता जा रहा है। वहीं अकाली दल के अंदर का असंतुष्ट खेमा भितरघात की तैयारी में ला रहा है। देश के अन्दर के हालातों को सीमापर से नियंत्रित करने का चक्र भी निरंतर गति पकड़ रहा है। खालिस्तान समर्थकों के

स्लीपिंग सेल्स को फिर से एक्टिव किया जा रहा है। कश्मीर में आतंकियों की संख्या में इजाफा करने के लिए सीमा पर से गुण अभियान चलाया जा रहा है। चीन की शह पर नक्सलवाद की चहलकदमी भी किसी से छुपी नहीं है। लाल सलाम का खुनी रंग अपनी मौजूदगी दिखाने को बेताब है। वहीं दूसरी ओर धर्म निरपेक्ष राष्ट्र की संवैधानिक इकाई के गठन में लगभग सभी राजनैतिक दल विधानसभा क्षेत्रों में जातिगत मतदाताओं के आधार को ही टिकट वितरण का सुविधाजनक फार्मूला रहे हैं। जातिगत भेद को मिटाकर सभी नागरिकों को समान अधिकार देने का दावा करने वाले कथित ठेकेदार ही जब जातिवाद को महाल देकर टिकटों का वितरण करेंगे, सम्प्रदायगत नेताओं को महाल देगे और फूट डालो, राग करो, की नीति अपनायें तो फिर

सिंहसन पर बैटने के बाद उनका समान सुछिण होना लगभग असम्भव ही है। उत्तर प्रदेश में योगी के द्वारा ब्राह्मणों को प्रभावहीन करने की नीति अब भारतीय जनता पार्टी के गले की हड्डी बन गई है। स्थाई कर्मचारियों और अधिकारियों को आर्थिक गति देने के बाद सविदाकर्मियों को प्रताड़ित करना भी पार्टी के लिए घातक सिद्ध हो रहा है। ऐसे में हिन्दुवादी ऐजेन्डा प्रदेश में पानी का बुलबुला बनता जा रहा है। सविदाकर्मियों की नाराजगी का खामियाजा भुगतने की स्थिति में पार्टी हट चुकी है। एक बार फिर योगी को ही प्रदेश का मुख्यमंत्री चेहरा बनाने के कारण कमल का पोषण समाप्त होना दिख रहा है। पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष से लेकर मुख्यमंत्री तक के आगेदे ठाकुर जाति के खास लोगों को रेवडी की तरह बांट दिये गये हैं। ऐसे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पुराने कदावर लोगों को केवल ब्राह्मण जाति का होने के कारण ही हाशिये पर पहुंचा देना, इस बार के चुनावी संग्राम में नकारात्मकता ही परेसता दिख रहा है। संघ के ऐसे नामची लोगों ने अपने आवासों से भितरघात करना शुरू कर दी है। उनके सम्पर्कों में छत्र जीवन से रहे सैकड़ों लोग आज समाजसेवी लोकप्रिय

व्यक्तित्व बनकर उभर चुके हैं। ऐसे लोकप्रिय व्यक्तित्वों ने एक आदर्श संघ कार्यकर्ता की उपेक्षा, अपमान और तिरस्कार अपनी जागती आंखों से देखा और जो नहीं देखा उसे संघ के उन कदावर नेताओं ने प्रकाशित कर दिया। इस प्रकाशन के बाद तो हाथी के दांतों की कहवत का अर्थ सोशल मीडिया पर भरा पड़ है। आज हालात यह हैं कि पंजाब में कांग्रेसी सिद्ध का इमरान-बाजवा प्रेम किसी से छुपा नहीं है तिस पर कैप्टन अमेन्दर सिंह के वक्तव्य ने यज्ञ में आहुति का काम किया है। इमरान की शिफारिश वाले मामले ने तो कांग्रेस की मंशा पर ही प्रश्नचिह्न अंकित कर दिये हैं। विपक्ष ने तो इस मुद्दे पर नेहरू-जिन्ना से लेकर सिद्ध-इमरान तक की कड़ियां जोड़ना शुरू कर दी हैं। केजरीवाल की कथित साफ-सुथरी छवि और योग्यता के साथ विकास माडल पर से आम नागरिकों का विश्वास उड़ता दिखने लगा है। अकाली दल का अपना अलग ही ऐजेन्डा है जिसे चन्द लोगों द्वारा अधिग्रहीत करने का खबरें फैल रही हैं। उत्तराखण्ड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बाद भी साधु-संतों को प्रताड़ित करने के मामलों में निरंतर बढ़ोतरी होने से हिन्दुत्व के आवरण में छेद होने लगे हैं। हाथी की चाल की मस्ती अभी सामने आना बाकी है। मायावती का मायाजाल अभी भी दलित वोटों से बाजी पलटने का दम भर रहा है।

बजट पर विशेष प्रतिक्रिया

तिलहन और फल सब्जी क्षेत्र के किसानों हेतु नए पैकेज कृषि अर्थव्यवस्था में मजबूती प्रदान करेंगे। किसानों और व्यापारियों हेतु लाभकारी सिद्ध होंगे। आत्मनिर्भर भारत के नए आयाम स्थापित होंगे ऐसा बजट प्रावधानों से स्पष्ट प्रतीत होता है। पेयजल हेतु विशेष प्रावधान जनता के सुगम स्वस्थ जीवन का आधार बनेगा। पोस्ट ऑफिस कोर बैंकिंग सिस्टम से जुड़ने से समाज के अतिम छोर पर खड़े व्यक्ति में बचत प्रवृत्ति बढ़ेगी, राष्ट्र को इसका लाभ मिलेगा।



राजकुमार भाटिया कृषि व्यापार विशेषज्ञ

162 साल पहले पेश हुआ था देश का पहला बजट

योगेश कुमार गोयल

संसद की दोनों सभाओं के समक्ष रखा जाने वाला वार्षिक वित्तीय विवरण केन्द्र सरकार का बजट कहलाता है, जो देश के विकास को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा कारक होता है।

%बजट% एक पुराने फ्रांसीसी शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है %पर्स%। भविष्य की योजनाओं और उद्देश्यों के आधार पर बजट एक निश्चित अवधि के लिए पूर्व निर्धारित राजस्व और व्यय का अनुमान होता है, जो भविष्य की वित्तीय स्थितियों को दर्शाता है और वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। यह एक ऐसा दस्तावेज है, जो प्रबंधन व्यवसाय के लिए अपने लक्ष्यों के आधार पर आगामी अवधि के लिए राजस्व और खर्चों का अनुमान लगाने के लिए बनाया जाता है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार, एक वर्ष का केन्द्रीय बजट, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहा जाता है, उस विशेष वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण होता है। केन्द्रीय बजट को राजस्व बजट तथा पूंजीगत बजट में वर्गीकृत किया जा सकता है। बजट के जरिये सरकार आर्थिक नीतियों को लागू करती है और हर साल पेश किए जाने वाले बजट का मुख्य उद्देश्य दुर्लभ संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना है। इस दस्तावेज में आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित आय और व्यय पर विस्तृत टिप्पणियां दी जाती हैं। बजट में शामिल प्रस्ताव संसद की स्वीकृति मिल जाने के बाद 1 अप्रैल से लागू हो जाते हैं, जो अगले साल 31 मार्च तक लागू रहते हैं।

बजट निर्माण की पूरी जिम्मेदारी वित्त मंत्रालय की ही होती है। वित्त



वर्ष 2022-23 के लिए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा एक फरवरी को बजट पेश किया गया। यह लगातार चौथा ऐसा अवसर है, जब

उन्होंने देश का आम बजट पेश किया है। वैसे यह जानना दिलचस्प है कि आगामी वित्त वर्ष के लिए जो केन्द्रीय बजट कुछ घंटों में पेश कर दिया जाता है, उसकी तैयारी करीब पांच माह पहले ही शुरू हो जाती है। इन तैयारियों के दौरान वित्त मंत्रालय केन्द्र सरकार के अन्य मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों के साथ मीटिंग करता है, जिसके आधार पर ही यह तय किया जाता है कि किस मंत्रालय अथवा विभाग को वित्त वर्ष के लिए कितनी रकम दी जाए। इन मीटिंग्स में तय होने के बाद एक ब्यूजिंट तैयार किया जाता है। बजट का प्रारूप तैयार हो जाने के बाद वित्त मंत्रालय तथा प्रधानमंत्री के बैठक में मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ मिलकर बजट का अवलोकन करते हैं और वित्त तथा राजस्व संबंधी नीतियों को निश्चित करते हैं। सम्पूर्ण

मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत होने के बाद केन्द्रीय बजट संसद में प्रस्तुत किया जाता है।

भारत में वित्त वर्ष प्रतिवर्ष एक अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को समाप्त होता है और बजट के विवरण में इस पूरे वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों तथा व्यय का ब्यौरा शामिल होता है। सरल शब्दों में कहे तो बजट आगामी वित्त वर्ष के लिए सरकार की वित्तीय योजना होती है, जिसके जरिये यह तय करने का प्रयास किया जाता है कि सरकार अपने राजस्व की तुलना में खर्च को किस हद तक बढ़ा सकती है। यह कवायद इसीलिए होती है क्योंकि सरकार को अपने राजकोषीय घाटे का एक लक्ष्य हासिल करना होता है।

बजट आमतौर पर तीन प्रकार का होता है- संतुलित बजट, अधिशेष बजट और घाटे का बजट। संतुलित बजट में आय और खर्च की मात्रा का समान होना जरूरी है जबकि अधिशेष बजट में सरकार की

आय खर्चों से अधिक होती है और घाटे के बजट में सरकार के खर्च उसकी आय के स्रोतों से अधिक होते हैं। सरकारी बजट तीन प्रकार के होते हैं, परिचालन या चालू बजट, पूंजी या निवेश बजट और नकदी या नकदी प्रवाह बजट। सरकारी बजट के प्रमुख साधनों में विभिन्न प्रकार के कर और राजस्व, सरकारी शुल्क, जुर्माना, लाभांश, दिए गए ऋण पर ब्याज आदि तरीके शामिल होते हैं।

बजट से जुड़े कुछ रोचक पहलुओं पर नजर डालना भी काफी दिलचस्प है। पहले बजट की कुछ प्रतियां छपती थी लेकिन अब बजट पूरी तरह डिजिटल हो गया है। 2016 तक फरवरी माह के अंतिम दिन आम बजट पेश किया जाता था किन्तु 2017 में तकालीन वित्तमंत्री कानूनी जेटली ने बजट पेश करने का दिन बदलकर 1 फरवरी कर दिया। 1999 तक बजट भाषण फरवरी के अंतिम कार्बिदस पर शाम पांच बजे पेश किया जाता था लेकिन 1999 में

यशवंत सिन्हा ने इसे बदलकर सुबह 11 बजे कर दिया। 2017 से पहले रेल बजट भी अलग से पेश किया जाता था लेकिन 2017 में उसे आम बजट में ही समाहित कर दिया गया।

1955 तक बजट केवल अंग्रेजी में ही पेश किया जाता था लेकिन उसके बाद इसे हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पेश करना शुरू कर दिया गया। 1950 तक बजट का मुद्रण राष्ट्रपति भवन में होता था किन्तु इसके लीक होने के बाद इसका मुद्रण दिल्ली की मिंटो रोड स्थित प्रेस में होने लगा और 1980 से वित्त मंत्रालय के अंदर सरकारी प्रेस में ही इसका मुद्रण होता है। 1947 से लेकर अब तक देश में 73 आम बजट, 14 अंतरिम बजट व 4 विशेष या मिनी बजट पेश किए जा चुके हैं।

वैसे भारत में बजट पेश करने का सिलसिला 162 वर्ष पहले शुरू हुआ था, जब 7 अप्रैल 1860 को ईस्ट इंडिया कम्पनी से जुड़े स्कॉटिश अर्थशास्त्री व नेता जेम्स विल्सन ने ब्रिटिश साम्राज्य के समक्ष पहली बार

भारत का बजट रखा था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट तत्कालीन वित्तमंत्री आर के फणमुगम चेट्टि ने 26 नवम्बर 1947 को पेश किया था, जिसमें कोई टैक्स नहीं लगाते हुए केवल अर्थव्यवस्था की समीक्षा की गई थी।

वैसे तो देश का बजट सदैव वित्तमंत्री ही पेश करते आए हैं लेकिन देश के इतिहास में तीन ऐसे अवसर भी आए, जब प्रधानमंत्री ने आम बजट पेश किया। बतौर वित्तमंत्री सर्वाधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नाम है, जिन्होंने 1962-69 के बीच 10 बार बजट पेश किया था। वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने संयुक्त मोर्चा सरकार में 1996 से 1998 तक और फिर यूपीए-1 तथा यूपीए-2 सरकार में कुल 9 बार, वित्तमंत्री प्रणव मुखर्जी ने इंदिरा सरकार में 1988 से 1984 तक और मनमोहन सिंह सरकार में 2009 से 2012 तक कुल 8 बार बजट पेश किया। यशवंत राव चव्हाण, सीखी देशमुख तथा यशवंत सिन्हा ने 7-7 बार जबकि मनमोहन सिंह और टीटी कृष्णामाचारी ने 6-6 बार बजट पेश किया।

इंदिरा गांधी ने पहली महिला वित्तमंत्री के तौर पर 1970 में बजट पेश किया था। 1977 में मात्र 800 शब्दों का सबसे छोटा भाषण वित्तमंत्री हीरुभाई मुलजीभाई पटेल ने जबकि शब्दों के लिहाज से कुल 18650 शब्दों का सबसे बड़ा बजट भाषण 1991 में मनमोहन सिंह ने दिया था। उसके बाद 2018 में अरुण जेटली ने 18604 शब्दों का बजट भाषण दिया था। सबसे ज्यादा देर तक बजट भाषण देने का रिकॉर्ड निर्मला सीतारमण के नाम है, जिन्होंने वित्त वर्ष 2020-21 का बजट पेश करते हुए 2 घंटे 42 मिनट तक बजट भाषण दिया था।

राष्ट्रीय उत्सव के नए आयाम

-डॉ. दिलीप अग्निहोत्री-

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय पर्वों पर औपचारिकता के निर्वाह तक सीमित नहीं रहते। राष्ट्रीय चेतना से जनमानस को जोड़ते हैं। देश के सुदूर क्षेत्रों तक इस भावना का विस्तार करते हैं। गणतंत्र दिवस समारोह का एक हफ्ते तक विस्तार किया गया। इसमें राष्ट्र नायकों के स्मरण के अवसर समाहित किया गए। इसके पहले नरेंद्र मोदी ने आजादी का अमृत महोत्सव प्रारंभ किया था। इसे अनेक स्तरों के समारोहों से सजाया गया। राष्ट्रीय राजधानी से लेकर गांवों व जनजातीय इलाकों तक इसका प्रकाश पहुंचाया गया। इसमें राष्ट्रभाव के अनेक उर्ध्वप्रसंग उजागर हुए।

इसके पहले नरेंद्र मोदी पंच सम्मानों को भी सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचा चुके थे। देश में गुमनामी में रहते हुए भी अनेक लोग विलक्षण कार्य करते हैं। नरेंद्र मोदी सरकार जहां ना पहुंचे रिव कहवत के अनुसूच उन लोगों तक पहुंच गईं। उनको पंच सम्मान मिलने लगे। इसवार मन की बात में नरेंद्र मोदी ने ऐसे लोगों का उल्लेख किया। देश के सुदूर क्षेत्रों में अनेक लोग समाज सेवा के विलक्षण कार्य करते रहे हैं। कुछ वर्ष पहले तक सरकारों का ध्यान उनकी तरफ जाता



नहीं था। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनते समय अपनी सरकार को गरीबों के प्रति समर्पित बताया था। अनेक सामाजिक, आर्थिक व लोक कल्याण के विषयों जैसे विचार पर अमल किया जा रहा है। इतना ही नहीं पिछले कुछ वर्षों से पंच सम्मानों में भी यह परिलक्षित है। राष्ट्रपति भवन में पंच सम्मान ग्रहण करने वाले वनवासी, ग्रामीण व अन्य निर्धन वर्ग के लोग भी मुख्याधार में दिखाई देने लगे हैं। मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पंच पुरस्कारों में नया अध्याय जुड़ा है। इसमें गुमनाम समाजसेवकों,

कलाकारों को भी शामिल किया गया। इस प्रकार यह प्रतिष्ठित पुरस्कार गांव ही नहीं वनवासी क्षेत्रों तक पहुंच गया है। इस संवर्धन में पिछले कुछ वर्षों की पंच पुरस्कार सूची देखना दिलचस्प है।

अब पंच सम्मान समारोह में अद्भुत दृश्य दिखाई देते हैं। अक्सर चित्र भी अपने में बहुत कुछ कह जाते हैं। जब कोई गरीब महिला राष्ट्रपति के निर पर आर्शोर्वांद का हाथ रखती है, जब ऐसे ही किसी अन्य सम्मानित व्यक्ति से प्रधानमंत्री हाथ जोड़ बतियाते हैं। कुछ वर्ष पहले तक ऐसी कल्पना भी मुश्किल थी।

अब परंपरा का रूप ले चुकी है। प्रतिवर्ष पंच सम्मान वितरण के समय ऐसा ही दृश्य रहता है। ऐसा ही चित्र प्रयागराज कुंभ में देखने को मिला था, जिसमें प्रधानमंत्री सफाईकर्मियों के पैर धो रहे हैं। काशी में वह सफाई व अन्य कर्मियों पर पुष्प वर्षा करते हैं।

देश के विभिन्न इलाकों में अनेक गुमनाम समाजसेवकों हैं। जिन्होंने समाज के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। धन- दौलत, पद, यश, वैभव किसी की चाह नहीं थी। मीडिया या प्रचार से दूर रहे, गुमनामी में अपना कार्य करते रहे। पहले इनकी ओर शासन का ध्यान नहीं जाता था। कोई पहाड़ तोड़ कर अकेले ही सड़क बनाता रहा। शासन का ध्यान उधर गया होता तो उनका कार्य आसान हो गया होता। लेकिन हार नहीं मानी। पहाड़ तोड़ कर मार्ग बनाकर ही दम लिया। इसी प्रकार अनेक लोग अपने अपने ढंग से समाजसेवा में जुटे हुए हैं। नरेंद्र मोदी ने ऐसे गुमनाम लोगों को पंच सम्मान देने का निर्णय लिया था। अब प्रतिवर्ष ऐसे लोगों को सम्मान पुरस्कार देने की परंपरा शुरू हुई।

इस बार का राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया गया।

सरकार ने तय किया है कि अब हर साल गणतंत्र दिवस का पर्व 23 से 30 जनवरी तक सप्ताह भर का होगा। समारोह 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती से शुरू होकर 30 जनवरी को शहीद दिवस तक चलेंगे।

राजधन पर भारतीय वायुसेना के 75 विमान और हेलीकॉप्टर भव्य फ्लाईपास्ट किया था। यह आजादी के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। धन- दौलत, पद, यश, वैभव किसी की चाह नहीं थी। मीडिया या प्रचार से दूर रहे, गुमनामी में अपना कार्य करते रहे। पहले इनकी ओर शासन का ध्यान नहीं जाता था। कोई पहाड़ तोड़ कर अकेले ही सड़क बनाता रहा। शासन का ध्यान उधर गया होता तो उनका कार्य आसान हो गया होता। लेकिन हार नहीं मानी। पहाड़ तोड़ कर मार्ग बनाकर ही दम लिया। इसी प्रकार अनेक लोग अपने अपने ढंग से समाजसेवा में जुटे हुए हैं। नरेंद्र मोदी ने ऐसे गुमनाम लोगों को पंच सम्मान देने का निर्णय लिया था। अब प्रतिवर्ष ऐसे लोगों को सम्मान पुरस्कार देने की परंपरा शुरू हुई।

इस बार का राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया गया।

शामिल था। नरेंद्र मोदी की देश में लोकप्रियता एक बार फिर प्रमाणित हुई। उनकी एक बात पर देश के एक करोड़ बच्चों ने पत्र लिख दिए। आजादी के अमृत महोत्सव के दुष्टित एक करोड़ से अधिक बच्चों ने अपने मन की बात, पोस्टकार्ड के जरिये लिखकर भेजी है।

मोदी ने मन की बात में भारतीय संस्कृति की व्यापकता का उल्लेख किया। कहा कि भारतीय संस्कृति अमेरिका कनाडा, दुबई, सिंगापुर, पश्चिमी यूरोप एवं जपान में बहुत लोकप्रिय है। भारतीय संस्कृति का लैटिन अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में भी बड़ा आकर्षण है। अर्जेंटीना में हस्तनापुर फाउंडेशन नामक एक संस्था है। यह फाउंडेशन अर्जेंटीना में भारतीय वैदिक परम्पराओं के प्रचार में जुटा है। हस्तनापुर फाउंडेशन के 40 हजार से अधिक सदस्य हैं और अर्जेंटीना एवं अन्य लैटिन अमेरिकी देशों में इसकी करीब तीस शाखाएं हैं। हस्तनापुर फाउंडेशन ने स्पेनिश भाषा में सी से अधिक वैदिक और दार्शनिक ग्रंथ भी प्रकाशित किये हैं। आश्रम में बारह मंदिरों का निर्माण कराया गया है। जिनमें अनेक देवी-देवताओं की मूर्तियां हैं। इनके केंद्र में अद्वैतवादी ध्यान स्थल है।

सार समाचार

गौशाला में सैकड़ों गायों की लाशें मिलने पर बोले दिग्विजय सिंह, सरकार पर लगाए आरोप

भोपाल। राजधानी भोपाल में बीजेपी नेत्री निर्मला देवी शाहिल्य की गौशाला में सैकड़ों गायों की लाशें मिलने में बड़ा खुलासा हुआ है। गौशाला में गायों को चूने का पानी पिलाकर मारा जा रहा था। वहीं उनके चमड़े और हड्डियों का इस्तेमाल व्यापार में होता था। जिसके बाद कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने गायों की लाशें मिलने पर सीधे सीएम शिवराज सिंह चौहान और विश्व हिंदू परिषद पर निशाना साधा है। दिग्विजय सिंह ने टवीट कर सरकार पर कई बड़े आरोप लगाए। दिग्विजय सिंह ने कहा कि सैकड़ों गो माता की हत्या करने वाली भाजपा और विश्व हिंदू परिषद संचालित गौशाला को शिवराज उर्फ मामा उर्फ मामू ने करोड़ों अनुदान दिया। गोसेवा नहीं, गो हत्या के लिए चमड़ा और हड्डियों के व्यापार के लिए। उन्होंने कहा कि यदि आरोपी गैर भाजपा या गैर हिंदू होता तो अब तक उस पर एनएफएआर दर्ज कर दी गई है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि अबतक गो हत्या का प्रकरण दर्ज नहीं किया गया है। कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। गो हत्या करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की लड़ाई कांग्रेस आखरी दम तक लड़ेगी। गृह मंत्री जी मौन क्यों हैं?

चुनाव आयोग का फैसला, 1000 लोगों की सभा को मिली इजाजत, 11 फरवरी तक बढ़ा रैलियों पर प्रतिबंध

नई दिल्ली। पांच राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। इन 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर शामिल हैं। हालांकि देश में कोरोना वायरस की तीसरी लहर भी अपने चरम पर है। कोरोना वायरस की रफ्तार को देखते हुए चुनाव आयोग ने चुनावी रैली और रोड शो पर रोक लगा रखी है। चुनाव आयोग ने 11 फरवरी तक रैलियों पर प्रतिबंध बढ़ा दिया है। हालांकि आज चुनाव आयोग की ओर से प्रचार के लिए राजनीतिक दलों को थोड़ी राहत जरूर दी गई है। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को 1000 लोगों के साथ चुनावी सभा करने की इजाजत दे दी है। इतना ही नहीं, अब 20 लोग डोर-टू-डोर कैंपेन भी कर सकते हैं। पहले इसकी संख्या 10 थी। इनडोर बैठक में भी अब 300 की जगह 500 लोग हिस्सा ले सकते हैं। ज्यादा लोगों के साथ रोड शो और चुनावी रैली पर अब भी पाबंदी लागू रहेगी। चुनाव एलेन के साथ ही आयोग की ओर से रोडशो और चुनावी रैली पर प्रतिबंध लगाई गई थी जिसे 31 जनवरी तक बढ़ा दिया गया था। निर्वाचन आयोग ने चुनावी राज्यों में टीकाकरण की रफ्तार को और बढ़ाने के लिए कहा है।

सिद्धू ने मजीठिया को बताया परचा माफिया, बोले- अगर वादे पूरे नहीं किए तो छोड़ दूंगा राजनीति

अमृतसर। पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सिंधिया पारा गर्मता जा रहा है। इसी बीच पंजाब कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू ने शिरोमणि अकाली दल (शिअद) नेता बिक्रम सिंह मजीठिया पर निशाना साधा और उन्हें परचा माफिया करार दिया। उन्होंने कहा कि मजीठिया ने कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है लेकिन मैंने किसी के खिलाफ एक भी मामला दर्ज नहीं कराया है। समाचार एजेंसी के मुताबिक, पंजाब कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि उन्होंने (बिक्रम सिंह मजीठिया) कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। मैंने किसी के खिलाफ एक भी मामला दर्ज नहीं कराया है। सभी जानते हैं कि कांग्रेस एक मजबूत और सुरक्षित सरकार होगी। हम बनाएंगे नया पंजाब। कांग्रेस में चल रही गुटबाजी को लेकर पूछे गए सवाल पर सिद्धू ने कहा कि कांग्रेस को कोई नहीं हरा सकता। खुद को कांग्रेस ही हरा सकती है। इसी बीच सिद्धू ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि अगर उनकी तरफ से किए गए वादे पूरे नहीं होते हैं तो वह राजनीति छोड़ देंगे।

सिद्धू के नाम एक भी उपलब्धि नहीं मजीठिया ने सिद्धू पर निशाना साधते हुए कहा था कि राजनीति में पिछले 18 वर्षों के दौरान नवजोत सिंह सिद्धू के नाम एक भी उपलब्धि नहीं है। वह और उनकी पत्नी शिअद-भाजपा और कांग्रेस सरकारों का हिस्सा रहे हैं, लेकिन अमृतसर पूर्व के लिए कुछ नहीं किया। इसीलिए लोगों ने मुझसे वहां से चुनाव लड़ने और उनके अहंकारी और स्वाधीन शासन को खत्म करने की अपील की है।

संसद में कोविड-19 संबंधी नियमों का उल्लंघन करते नजर आए कई सांसद

नयी दिल्ली। संसद के बजट सत्र के पहले दिन, दोनों सदन की संयुक्त बैठक में सोमवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के दौरान विभिन्न दलों के कई सांसद कोविड-19 से बचाव के लिए निर्धारित सामाजिक दूरी बनाए रखने के अहम नियम का उल्लंघन करते देखे गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड्गे, शीर्ष केन्द्रीय मंत्री और विभिन्न दलों के पहली दो पंक्तियों में बैठे सांसदों ने सामाजिक दूरी के नियम का पालन किया, लेकिन उनके पीछे की पंक्तियों में बैठे कई सदस्यों ने ऐसा नहीं किया। तीसरी पंक्ति में कई केन्द्रीय मंत्री भी बैठे थे। केन्द्रीय कक्ष की कुछ बेंच में जहां पांच लोगों के बैठने की जगह थी, वहां सात सांसद बैठे दिखे। इस दौरान कई सांसद बात करते समय मास्क उतारते हुए नजर आए। कोविड-19 वैश्विक महामारी की तीसरी लहर के दौरान संक्रमण के मामले बढ़ने के बाद सांसदों के केन्द्रीय कक्ष गैलरी के साथ-साथ लोकसभा और राज्यसभा कक्षों में बैठने की व्यवस्था की गई है। बजट सत्र के दौरान संसद की कार्यवाही दो पालियों में होगी। सुबह राज्यसभा की और शाम को लोकसभा की कार्यवाही होगी।

सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर हुई कोरोना संक्रमित, बयान में कहा था- गोमूत्र पीने से कोई संक्रमण नहीं होता

नयी दिल्ली। भाजपा नेता और भोपाल से सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आयी है। इस बात की जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से दी है। उन्होंने टवीट किया आज, मेरी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मैं डॉक्टर की देखरेख में हूँ। पिछले 2 दिनों में मेरे सफरों में आने वाले सभी लोगों से आग्रह किया जाता है कि वे सतर्क रहें और यदि आवश्यक हो तो परीक्षण भी करवाएं। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी स्वास्थ्य रहे।

राष्ट्रपति का अभिभाषण सिर्फ एक वर्ष का एजेंडा नहीं, भारत के लिए एक 'भविष्य की दृष्टि': नड्डा

नयी दिल्ली। (एजेंसी)

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष जे पी नड्डा ने सोमवार को कहा कि बजट सत्र के पहले दिन संसद के संयुक्त अधिवेशन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का अभिभाषण सिर्फ एक वर्ष का एजेंडा नहीं है बल्कि भारत के लिए एक 'भविष्य की दृष्टि' है। उन्होंने मिलसिलेवार टवीट कर कहा कि राष्ट्रपति कोविंद का अभिभाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का देश के विकास की दूरदृष्टि की रूपरेखा है। अभिभाषण में सरकार के विकास कार्यों के सभी आयामों का विस्तार से उल्लेख करने के लिए राष्ट्रपति का धन्यवाद करते हुए नड्डा ने कहा, 'यह एक साल का एजेंडा नहीं है बल्कि भारत के लिए एक भविष्य की दृष्टि है।' उन्होंने कहा, 'यह भारत के पुनर्निर्माण की रूप रेखा है, जिसमें स्पष्ट है कि आजादी के अमृत महोत्सव काल में हम कैसा भारतवर्ष चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार हर क्षेत्र में एक सशक्त भारत के निर्माण की ओर तेज गति से चल रही है।' नड्डा ने कहा कि मोदी सरकार ने अत्यंत प्रयासों से ही भारत को कोविड प्रबंधन, तीव्र गति से टीकाकरण, गरीबों



को मुफ्त राशन, किसानों के बेहतर भविष्य, महिला सशक्तिकरण एवं देश के हर वर्ग के उत्थान के लिए समर्पित भाव से काम किया है। उन्होंने कहा, 'आज भारत में सामाजिक न्याय के साथ सभी को समान अवसर मिल रहा है।' संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि सरकार के अथक प्रयासों से ही भारत एक बार फिर से दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती

अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और सबका प्रयास' के मंत्र पर चलते हुए अगले 25 वर्ष के लिए मजबूत बुनियाद पर तेजी से काम कर रही है और इस बुनियाद का सबसे महत्वपूर्ण संकल्प एक सर्व-समावेशी, सर्व-हितकारी, सशक्त भारत का निर्माण और देश की आत्म-निर्भरता है।

नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 126 से घटकर 70 रह गई: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद

नयी दिल्ली। (एजेंसी)

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सोमवार को कहा कि देश में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या में कमी आई है और इनकी संख्या घटकर 126 से 70 रह गई है। बजट सत्र के पहले दिन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि कार्बी-आंगलों के दशकों पुराने विवाद को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार, असम की राज्य सरकार एवं कार्बी समूहों के बीच समझौता हुआ है और इससे इस क्षेत्र में शांति और खुशहाली का एक नया अध्याय शुरू हुआ है। उन्होंने कहा, 'सरकार द्वारा किए



गए प्रयासों से आज देश में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या भी 126 से घटकर 70 रह गई है।' केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी ने 21 सितंबर 2020 को राज्यसभा को सूचित किया था कि 11 राज्यों के 90 जिलों को वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित हैं

और वह केन्द्रीय गृह मंत्रालय की सुरक्षा संबंधी व्यव योजनाओं के अधीन है। रेड्डी ने यह भी कहा था कि वर्ष 2019 में वामपंथी उग्रवाद की घटनाएं 61 जिलों में दर्ज की गई थी जबकि वर्ष 2020 के पूर्वार्ध में 46 जिलों में घटनाएं दर्ज की गईं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों

बच्चों की सुरक्षा केन्द्रीय बजट का केंद्र बिंदु होना चाहिए, बाल अधिकार संगठनों की मांग

नयी दिल्ली। (एजेंसी)

बाल अधिकार संगठनों का कहना है कि बच्चों की सुरक्षा केन्द्रीय बजट का केंद्र बिंदु होना चाहिए और बाल श्रम के उन्मूलन के लिए आवंटन में वृद्धि और सामाजिक सुरक्षा-तंत्र को मजबूत करने में अधिक निवेश होना चाहिए। संगठनों ने यह भी कहा कि प्रभावी रोकथाम तंत्र की गति को तत्काल आधार पर तेज करने की आवश्यकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट सत्र के पहले दिन संसद के संयुक्त अधिवेशन में कहा कि बच्चों के बचपन में बच्चों के लिए बजट आवंटन के कुल प्रतिशत हिस्से में सुधार 2020-21 के स्तर पर बहाल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, 'यहां यह उल्लेख करना जरूरी है कि बच्चों के कल्याण के लिए आवंटित केन्द्रीय बजट का प्रतिशत हिस्सा 3.16 प्रतिशत (2020-21) से घटाकर 2.46 प्रतिशत (2021-22) कर दिया गया है। यह पिछले 11 वर्षों में बच्चों के कल्याण के लिए आवंटित, बजट का

सबसे कम हिस्सा है। उन्होंने कहा, इसके अलावा, अगर हम पिछले दो वर्षों के बजट आवंटन को देखें, तो बच्चों के कल्याण के लिए आवंटित कुल बजट में 2020-21 की तुलना में 2021-22 में 11 प्रतिशत की गिरावट आई है। माथुर ने कहा कि एक व्यापक राष्ट्रीय कार्य योजना के साथ बाल श्रम के उन्मूलन के लिए प्रभावी रोकथाम तंत्र की गति को आगे बढ़ाने में बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए बढ़ा हुआ बजटीय आवंटन शामिल है, जो राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) के समग्र बजट मद का एक हिस्सा है। चाइल्ड राइट्स एंड यू, की मुख्य कार्यकारी अधिकारी पूजा मारवाह ने कहा कि बच्चों को किसी भी विकास विमर्श के केंद्र में रखा जाना चाहिए और यह केन्द्रीय बजट का केंद्र बिंदु होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी ने बच्चों को शारीरिक, मानसिक रूप से प्रभावित तो किया ही, उन्हें पारिवारिक संकट, प्रवास, अलग-थलग रहने, पढ़ाई में बाधा तथा अन्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ा है।

के कल्याण के लिए आवंटित, बजट का

आप नहीं जान पाएंगे राहुल गांधी कब छुट्टी पर चले जाएंगे और गोवा सरकार अस्थिर हो जाएगी: शाह

पणजी (एजेंसी)

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को गोवा में युवाओं से उनके बेहतर भविष्य के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का समर्थन करने की अपील की और कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि युवाओं को कभी पता नहीं चलेगा कि राहुल गांधी कब छुट्टी पर चले जाएंगे और शाह ने कब अस्थिरता पैदा हो जाएगी। वास्को शहर में भाजपा के सोशल मीडिया कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत के दौरान शाह ने कहा कि केवल भाजपा ही युवाओं के बेहतर भविष्य की गारंटी दे सकती है। गोवा में 14 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले शाह एक दिवसीय दौरे पर आए थे। शाह ने कहा कि गोवा अगले पांच साल में 'एजुकेशन हब' में तब्दील हो जाएगी, जिसकी योजना पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत मनोहर परिकर



और मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने तैयार की थी। शाह ने कहा कि दो महीने पहले ही गोवा में 'फॉरसिक साइंस यूनिवर्सिटी' की नींव रखी गई थी। केवल भाजपा ही युवाओं के बेहतर भविष्य की गारंटी दे सकती है। गोवा में 14 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले शाह एक दिवसीय दौरे पर आए थे। शाह ने कहा कि गोवा अगले पांच साल में 'एजुकेशन हब' में तब्दील हो जाएगी, जिसकी योजना पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत मनोहर परिकर

अवसर होंगे। इसलिए, मैं कहता हूँ, आप सभी को कहीं (किसी अन्य राजनीतिक दल) नहीं जाना होगा क्योंकि अगर आप कांग्रेस का समर्थन करते हैं तो आपको कभी भी पता नहीं चलेगा कि राहुल बाबा कब छुट्टी पर जाएंगे और गोवा सरकार अस्थिर हो जाएगी। शाह प्रोक्ष रूप से गोवा में कांग्रेस की राजनीतिक स्थिति की ओर इशारा कर रहे थे। पिछले पांच वर्षों में दलबदल के कारण कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है।

महाराष्ट्र: कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर गोडसे की तस्वीर जलायी



ठाणे। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रविवार को महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे की तस्वीर जलायी और विरोध प्रदर्शन किया। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर यह विरोध प्रदर्शन कांग्रेस की भिवंडी इकाई के प्रमुख राशिद ताहिर के नेतृत्व में किया गया। प्रदर्शनकारियों ने गोडसे के खिलाफ और गांधी की प्रशंसा में नारे लगाए। ताहिर ने पत्रकारों से कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि नाथूराम गोडसे पर आने वाली फिल्म के जरिए उसका महिमामंडन किया जा रहा है। उनका इशारा हिंदी फिल्म व्हाई आई फिल्टर गांधी की ओर था जिसमें राकापा सांसद और अभिनेता डॉ अमोल कोल्हे गोडसे की भूमिका निभा रहे हैं। फिल्म की शूटिंग 2017 में हुई थी। ताहिर ने सरकार से फिल्म की रिलीज रोकने का आग्रह किया। ठाणे में, राकापा के वरिष्ठ नेता एवं महाराष्ट्र के मंत्री जितेंद्र आव्हाड और कांग्रेस की शहर इकाई के प्रमुख विक्रम वडवाने ने महात्मा गांधी उद्यान में गांधीजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी।

कड़वा सच यह है कि बहुत सारे भारतीय महिलाओं को इंसान नहीं समझते: राहुल गांधी

नयी दिल्ली। (एजेंसी)



कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली में 20 वर्षीय महिला के साथ कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार और उसकी पिटाई की घटना को लेकर सोमवार को कहा कि यह कड़वा सच है कि बहुत सारे देशवासी महिलाओं को इंसान नहीं समझते। उन्होंने टवीट किया, '20 वर्षीय महिला की निर्ममता से पिटाई किए जाने संबंधी वीडियो हमारे समाज का बहुत वीथल्स चेहरा सामने लाता है। कड़वा सच यह है कि बहुत सारे भारतीय, महिलाओं को इंसान नहीं समझते।' गौरतलब है कि पूर्वी दिल्ली की एक कॉलोनी में पड़ोसियों द्वारा 20 वर्षीय महिला का कथित तौर

पर अपहरण करने, उससे सामूहिक बलात्कार करने और सड़क पर उसे निर्वस्त्र घुमाने का मामला सामने आया है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने पीड़िता की छोटी बहन का भी उत्पीड़न किया था। पुलिस मामले में पहले ही नौ लोगों, आठ महिलाओं और एक पुरुष को गिरफ्तार कर चुकी है। पीड़िता के खिलाफ अपराध में कथित भूमिका के लिए तीन नाबालिग लड़कों को भी हिरासत में लिया गया है।

मोदी-योगी सरकारों में 'घर जमाई' बन गई है 'डायन' महंगाई: रणदीप सुरजेवाला

लखनऊ। (एजेंसी)

कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने सोमवार को महंगाई के मुद्दे पर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि जो 'डायन' महंगाई है वह मोदी (प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी) - योगी (मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ) सरकारों में 'घर जमाई' बन गई है। उन्होंने महंगाई से मुक्ति के लिए भाजपा की सरकार से मुक्ति पाने का अनुरोध किया। कांग्रेस नेता सुरजेवाला ने सोमवार को यहां कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में महा महंगाई, भाजपा लाई पुस्तक का लोकार्पण करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में 2014 में कांग्रेस सरकार और सात वर्षों में

बढ़ी महंगाई का फर्क समझाते हुए कहा कि जो डायन महंगाई है, वह मोदी-योगी सरकारों में घर जमाई बन गई है। उन्होंने केंद्र और राज्य की भाजपा नीत सरकारों पर प्रहार करते हुए दावा किया, एक तरफ देश के लोगों को महंगाई की आग में झोंक दिए तो दूसरी तरफ सात साल में भाजपा को संपत्ति सत्तारूढ़ मोदी की 780 करोड़ से बढ़कर 4850 करोड़ हो गयी यानी साढ़े पांच सौ प्रतिशत बढ़ गई और हम दो, हमारे दो की संपत्ति हर रोज एक हजार करोड़ बढ़ रही है।' एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, मैं किसान हूँ और इस देश के 62 करोड़ किसान की पीड़ा में मन को कचोटती है, यह पहली सरकार है जिसने खाद,

कीटनाशक दवाइयों पर कर लगाया है। ट्रैक्टर और खेती के उपकरणों पर भी कर लगा दिया है। उन्होंने दावा किया कि नरेंद्र मोदी और अजय सिंह बिष्ट (योगी आदित्यनाथ का संत होने से पहले का नाम) ने साढ़े 17 लाख करोड़ रुपये किसान की जेब से निकाला है। सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि मोदी जी अलग और अजय सिंह बिष्ट जनता की अलग जेब काटते हैं और दोनों जेब काटते हैं। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि महंगाई मुद्दा है लेकिन कई बार राजनेताओं के शोरगुल में यह दिखता नहीं है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में कांग्रेस की लड़ाई महंगाई और बेरोजगारी से है और पहली लड़ाई उनसे है जो

मटाधीश दिल्ली और लखनऊ दोनों में सात साल से और एक पांच साल से लोगों की जिंदगियां लूट रहे हैं, पहली लड़ाई उनसे है। चुनाव में सत्तारूढ़ दल के प्रचार प्रसार पर कटाक्ष करते हुए सुरजेवाला ने कहा, चुनाव और श्मशान, कब्रिस्तान, तमंचा और लड़के, एक दूसरे के लिए गाली गलौज और हर बार की तरह फिर विभाजन की कोशिश सब चीजें उग्र के चुनाव में चल रही हैं सियाव उनके जिनका उग्र और देश की जिंदगी पर असर पड़ता है-महंगाई और बेरोजगारी। उन्होंने कहा, 'इन दोनों (महंगाई-बेरोजगारी) को तमंचे से मारिए या इत्र छिड़क मारिए, कैसे मारेंगे, यह सरकार

की जिम्मेदारी का हिस्सा है, उन्हें श्मशान में जलाइए या कब्रिस्तान में दफनाइए, पर भगवान के लिए, ईश्वर के लिए इसका हल निकालिए क्योंकि यही लोगों की जिंदगी का मसला है। महंगाई पर जारी कांग्रेस की पुस्तिका की चर्चा करते हुए सुरजेवाला ने कहा कि महा महंगाई, भाजपा लाई पुस्तक का शीर्षक इसलिए दिया क्योंकि 'यही इस देश और प्रदेश का सत्य है। इसलिए हम कहते हैं कि भाजपा को हराइए, महंगाई पर विजय पाइए। कांग्रेस नेता ने एक शेर पढ़ा, जिन्हें सौंपी थी रोशनी की रहनुमाई, बुझाकर चिराग वो दे रहे हैं उजाले की दुहाई और कहा कि मोदी और योगी सरकार जब यह शब्द जुवां

पर आते हैं तो लोगों का ख्याल सीधे खाली जेब पर जाता है और यह बात उठती है कि एक तो आमदनी कर दी कम और दूसरी तरफ महंगाई का गम। उन्होंने कहा, सुबह उठकर जब लोग चाय बनाते हैं तो गैस का सिलेंडर एक हजार रुपये पा रहे हैं, खाने का तेल दो सौ रुपये, और दफ्तर जाते हैं तो पेट्रोल सौ रुपये में भरते हैं और घर लौटते हुए राशन खरीदते तो कई गुना दाम चुकाते हैं।' उन्होंने कहा, मोदी और योगी की सरकार जिस जनता के नमक की सोंगंध खाकर सता में आई थी उसकी कीमत भी दोगुनी कर दी। महंगाई का आंकड़ा प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा, लोग सुकून से अब एक प्याला चाय नहीं पी सकते हैं

व्योक्ति 2014 में जब कांग्रेस की सरकार गई तो जो चाय 130-140 रुपये किलो थी, वह आज 400-500 रुपये किलो हो गई। दाल, चना, राजमा, टमाटर, अरहर, मटर, मूंग सब कुछ लोगों की थाली से दूर होता जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश के लोगों की जेब काटी जा रही है पर भाजपा की संपत्ति बढ़ रही है। सुरजेवाला ने कहा कि पिछले 12 साल में सबसे ज्यादा 14.23 प्रतिशत थोक महंगाई बढ़ गई है और खुदरा महंगाई लगभग छह प्रतिशत बढ़ी है। उन्होंने दावा किया कि मोदी सरकार ने पिछले सात साल में पेट्रोल डीजल पर कर लगाकर 24 लाख करोड़ रुपये कमाया है, अगर 2014 में

कांग्रेस सरकार के समय की एक्?साइज ड्यूटी हो तो आज पेट्रोल की कीमत लखनऊ में साढ़े 26 रुपये कम हो जाएगी और डीजल की कीमत सवा 25 रुपये कम हो जाएगी। उन्होंने बड़ी हुई महंगाई का विस्तार से ब्यौता देते हुए रेल किराये में वृद्धि का उदाहरण दिया और कहा कि कांग्रेस के समय 32 पैसे प्रति किलोमीटर रेल भाड़ा था लेकिन मोदी जी और योगी ने उस भाड़े को एक रुपये दस पैसे प्रति किलोमीटर कर दिया है, यानी 343 प्रतिशत की वृद्धि हो गई। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि अब तक जो भी टीके सरकारों ने लगवाए मुफ्त लगाए लेकिन पहली बार मोदी जी ने टीका लगवाने के पैसे लिए।

एसपी के निर्देशन पर : ऑपरेशन प्रहार के तहत

आगामी विधानसभा चुनाव को सक्थाल शांतिपूर्ण स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान हेतु बाटी विश्वास पर्ची

गांवों कस्बों में चौपाल लगाकर विश्वास पर्ची बांटकर मतदाताओं को स्वतंत्र मतदान करने हेतु किया जागरूक



विश्वास पर्ची		संख्या
हाथरस पुलिस		113
आप सभी को सूचित किया जाता है कि आगामी विधानसभा चुनाव-2022 में आप निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग अपनी इच्छा के अनुसार करें। विधानसभा चुनाव में यदि कोई व्यक्ति आपको मतदान करने से डराये, धमकाये या धन, वस्तु, शराब आदि का प्रलोभन दे अथवा आपको मताधिकार के प्रयोग से बर्हिदा रखने का किसी प्रकार का उपक्रम करता है, तो पीछे लिखे नम्बर पर सूचित कर सकते हैं।		
संयोजक	945403378	
उपसंयोजक	945403379	
उपसंयोजक	945403380	
उपसंयोजक	945403381	
उपसंयोजक	945403382	
उपसंयोजक	945403383	
उपसंयोजक	945403384	
उपसंयोजक	945403385	
उपसंयोजक	945403386	
उपसंयोजक	945403387	
उपसंयोजक	945403388	
उपसंयोजक	945403389	
उपसंयोजक	945403390	
उपसंयोजक	945403391	
उपसंयोजक	945403392	
उपसंयोजक	945403393	
उपसंयोजक	945403394	
उपसंयोजक	945403395	
उपसंयोजक	945403396	
उपसंयोजक	945403397	
उपसंयोजक	945403398	
उपसंयोजक	945403399	
उपसंयोजक	945403400	

संवाददाता

हाथरस। आगामी विधानसभा चुनाव- के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने जनपद वासियों को सक्थाल शांतिपूर्ण एवं स्वतंत्र निष्पक्ष मतदान करने हेतु विश्वास पर्ची- जारी कर दी। साथ ही विश्वास पर्ची बांटे के निर्भीक होकर मतदान कराने के लिए जागरूक करने की हाथरस पुलिस की अहम पहल है। जिसके माध्यम से मतदाताओं को बड़ चढ़कर मतदान करने हेतु जागरूक प्रोत्साहित किया जायेगा तथा यदि कोई व्यक्ति लोगों को मतदान करने से डराएगा धमकाएगा या धन वस्तु शराब

आदि का प्रलोभन देता है अथवा प्रधान प्रत्याशियों या ग्रामवासियों को किसी प्रकार की समस्या चुनाव के दौरान होती है तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस प्रशासन को विश्वास पर्ची के पीछे लिखे नंबरों पर दे सकेंगे साथ ही आमजन को अवगत करवाया जायेगा कि यदि कोई व्यक्ति विधानसभा चुनाव में मतदान करने से डराये धमकाये या धन वस्तु शराब

आदि का प्रलोभन दे तो उसकी सूचना तत्काल पुलिस प्रशासन को विश्वास पर्ची के पीछे लिखे नंबरों पर निर्भीक होकर दें। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूर्णतया गुप्त रखी जायेगी तथा ऐसे अराजकता फैलाने का प्रयास करता है अथवा अन्य किसी प्रकार से लोगों को परेशान करना है तो उसकी सूचना भी पुलिस प्रशासन को दें। इसके चुनाव के दौरान होने वाली अप्रिय घटना की आशंका या कोई विवाद होने के पहले ही घटनाओं को रोका जा सकेगा और जनपद में शान्तिपूर्ण वातावरण में निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न कराया जायेगा।

निर्माणाधीन भवन को लेकर कुशवाह समाज की हुई बैठक



संवाददाता

हाथरस। सासनी कुशवाहा क्षत्रिय समाज सेवा ट्रस्ट की एक आवश्यक बैठक ग्राम बिजाहरी स्थित ट्रस्ट के द्वारा निर्माणाधीन कुशवाहा सामुदायिक भवन के निकट पूर्व प्रधानपति संतोष कुशवाह के आवास पर आहूत की गई। जिसमें तमाम समाज सेवियों ने समाज के उत्थान हेतु अपने विचार रखे। सोमवार को आहूत बैठक में

निर्माणाधीन भवन को लेकर हुई बैठक में वक्तों ने बताया कि ट्रस्ट द्वारा इस भवन का निर्माण कराया जा रहा है। जिसमें कुशवाहा क्षत्रिय समाज के कार्यक्रमों को अयोजन हेतु कहीं दूसरी जगह नहीं जाना पड़ेगा। इस भवन निर्माण का कार्य ज्यों पर है। इसके अलावा ट्रस्ट की योजनाओं पर भी विचार विमर्श किया गया। इस दौरान भीमपाल सिंह कुशवाहा, संतोष कुशवाहा ट्रस्ट के अध्यक्ष सोनपाल सिंह कुशवाहा आदि मौजूद थे।

एण्ट्री शुल्क न देने पर आरटीओ पर जबरन चालान करने का आरोप

व्यापारियों ने लामबंद होकर जताया विरोध

संवाददाता

ललितपुर। जिला स्माल स्कूल इन्स्टीट्यूट की एक आवश्यक बैठक प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष महेंद्र जैन मयूर के मुख्य आतिथ्य एवं जिला महामंत्री अनिल जैन की अध्यक्षता में सम्पन्न की गयी। बैठक का संचालन दानवीन सिंह और मुकेश परवार ने किया। बैठक में प्रमुख रूप से प्रदेश संगठन मंत्री अशोक अनौर, सतीश जैन बंटी, सेवाराम चैधरी, मनोज जैन छप्पन, नगर अध्यक्ष महेश जैन मोनू, नगर महामंत्री पंकज बिधा आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। अयोजित बैठक में उद्यमियों की समस्याओं का उद्घोषित संगठन को और अधिक सक्रिय करने पर विचार विमर्श किया गया। अयोजित बैठक में खनिज अधिकारी द्वारा किये गये व्यापारियों से अपमान जनक व्यवहार दिन प्रतिदिन विलुप्त होती जा रही है। फैंक्ट्रियों को सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक ड्यूटी का लाभ न देने,



चन्देरा सेक्टर में स्थायी रूप से स्टेशन की स्थापना एवं लखन मैन की स्थायी ड्यूटी निर्धारित करने, एवं एण्ट्री शुल्क न दिये जाने पर आरटीओ टीम द्वारा उनका चालान किये जाने आदि समस्याओं पर चर्चा करते हुए आदि समस्याओं का निराकरण कराय जाने की मांग की गयी। अयोजित बैठक में खनिज अधिकारी शशांक शर्मा ने गणतन्त्र दिवस की ध्वज रात्रि में मनोज बाजपेयी की फैंक्ट्री, शिवांशी ग्रेनाइट फैंक्ट्री में दिनांक 26 जनवरी 2022 की अर्द्धरात्रि में फैंक्ट्री जबरन खुलवाकर चैकीदार एवं अन्य कर्मचारियों से

प्राकट्य स्थली जलालाबाद का नाम हो : परशुराम पुरी



राष्ट्रीय अटल्य को सौंप ज्ञापन ब्राह्मण व सर्वर्ण समाज की समस्याओं की उठाई मांग

संवाददाता

हाथरस। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को ब्राह्मण एवं तथाकथित सर्वर्णों के साथ हो रहे अत्याचार अपमान उन्नीडन अन्याय व भेदभाव के संबंध में एक ज्ञापन अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा ने सौंपते हुए श्री नड्डा से ब्राह्मण समाज सर्वर्ण समाज व देश के हित में उपरोक्त मांगों को पूरा करने

में आज सहयोग की अपेक्षा की है ज्ञापन में उन्होंने कहा है कि ब्राह्मणों सहित सभी सर्वर्णों की वास्तविक स्थिति का पता लगाने हेतु शक्ति सम्पन्न केन्द्रीय व प्रदेशीय आयोग का गठन किया जाये। साथ ही भगवान परशुराम प्राकट्य दिवस पर अवकाश जिसे पूर्व सरकार ने घोषित किया था और योगी सरकार ने सत्ता में आते ही निरस्त कर दिया उसको शीघ्रतापूर्वक घोषित किया जाये। साथ ही मन्दिरो में सेवा करने वाले सभी पुजारी व पुरोहितों को कम से कम 5000 रुपये बतौर मासिक भत्ता दिया जाये। साथ ही उत्तर प्रदेश में हुई ब्राह्मणों की

अवैध देशी शराब व यूरिया सहित गिरफ्तार



संवाददाता

हाथरस सासनी कोतवाली पुलिस ने एक युवक को अवैध रूप से बिन्की के लिए ले जा रही देशी शराब सहित गिरफ्तार कर बंद किया है। एसएचओ सतेन्द्र सिंह रावव के अनुसार वह पुलिस कप्तान विनीत जायसवाल के आदेशानुसार विधान सभा चुनाव 2022 के दृष्टिगत जनपद में जारी आचार संहिता के अनुपालनार्थ एवं अवैध शराब के निर्माण तथा बिन्की पर अंकुश लगाये जाने वाले ऑपरेशन प्रहार के तहत कम्पा में गप्त पर तभी उन्हें सूचना मिली कि एक युवक अवैध रूप से बिन्की हेतु एक थैले में शराब के कुछ पैवा ले जा रहा है एसएचओ ने सूचना को गभीरता से

लेते हुए मुखबिर द्वारा बताई जगह पर अलीगढ़ रोड स्थित बजाज एजेंसी के पीछे से पहुंची तो वहां मौजूद युवक पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस ने भी पीछा कर दौड़ लगाते हुए आरोपी को दबोच लिया और कोतवाली ले आई। जहां उसकी जामा तलाशी में पुलिस ने मिलावटी देशी शराब बेचने वाले तस्कर से कब्जे से बीस क्वार्टर देशी शराब व एक किलो यूरिया बरामद किया। पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को अपना नाम सोबी पुत्र मुख्तयार खॉं निवासी मोहल्ला आशानगर बताया है। वहीं पुलिस ने विभिन्न धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया है। आरोपी को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में एसएचओ के साथ कम्पा इंचार्ज एसआई सतीश कुमार सिंह, कांस्टेबल अमित कुमार, पवन कुमार, उमम सिंह आदि मौजूद थे।

शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए करेंगे काम : खटीक

ललितपुर। बहुजन समाज पार्टी से 227 महरौनी विधानसभा क्षेत्र की अधिकृत प्रत्याशी किरन खटीक ने सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंच कर रिटर्निंग ऑफिसर महरौनी के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। अपने पुत्र जितेंद्र खटीक, राजकुमार खटीक व मनोज खटीक के साथ नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंची किरन खटीक ने महरौनी क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने पर बल दिया। नामांकन पत्र दाखिल करके लौटी बसपार प्रत्याशी किरन खटीक ने कहा कि महरौनी विधानसभा क्षेत्र में आज भी मूलभूत समस्याओं का अम्बार है। इन समस्याओं को जड़मूल से निस्तारित करने के लिए एक प्लेटफार्म की आवश्यकता होती है, जिसके लिए वह चुनावी मैदान में हैं। कहा कि उनका परिवार सदैव महरौनी क्षेत्र की जनता के सुख-दुख में शामिल रहता है और आगे भी रहेगा। जितेंद्र रमेश खटीक ने कहा कि 227 महरौनी विधानसभा क्षेत्र में मुख्य दो उद्देश्य लेकर वह मैदान में हैं, जिनमें शिक्षा और स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। कहा कि बच्चों को बेहतर शिक्षा और युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए महरौनी में ही व्यवस्था करायी जायेगी। वहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अस्पतालों को बेहतर सुविधाओं से लैस करने की दिशा में कार्य किया जायेगा। कहा कि महरौनी विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव की जनता को खुशहाल बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया जायेगा।

बसपा : किरन के समर्थन में जनसंपर्क तेज

ललितपुर। 227 महरौनी विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी की अधिकृत प्रत्याशी किरन खटीक के समर्थन में उनके पुत्र समाजसेवी मनोज रमेश खटीक ने सोमवार को दर्जनों ग्रामीण अंचलों में पहुंच कर तृफानी जनसंपर्क किया। निर्वाचन आयोग से जारी गाइड लाइन का अनुपालन करते हुये टोली बनाकर गांव-गांव पहुंचे, जहां उन्होंने बुजुर्गों, महिलाओं का आशीर्वाद लिया तो वहीं युवाओं से मतदान के लिए अपील की। समाजसेवी मनोज रमेश खटीक 227 महरौनी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम गिदवाहा, कारीटोन, सुनौनी, भीकमपुर, हीरपुर, गिरार, तिसगना, इकौना, पीड्डा, चैका इत्यादि ग्रामीण अंचलों में पहुंचे। उन्होंने कहा कि महरौनी क्षेत्र के चहुंमुखी विकास के लिए बहुजन समाज पार्टी प्रतिबद्ध है। महरौनी क्षेत्र के प्रत्येक गांव में आवागमन के लिए पक्की सड़क निर्माण, शुद्ध पेयजल, बच्चों को शिक्षा के लिए बेहतर विद्यालय व स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अस्पतालों में बेहतर व्यवस्थाओं को कराने के लिए कार्य किया जायेगा। साथ ही युवाओं को रोजगार के अवसर तराशे जायेंगे। इस दौरान फईम रजा, प्रभुदयाल, शुभम राजा, रामदयाल, धीरवी कुमार, पुष्येन्द्र सिंह लोधी, प्रभुदयाल कुशवाहा, जमील खान, भगवानदास प्रजापति, प्यारेलाल, हरिराम सहरिया, जगदेव सिंह राजा आदि मौजूद रहे।

समाज से मजबूत चेहरा रहल चुनावी मैदान में

ललितपुर। वर्तमान में चल रहे विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 को लेकर ललितपुर में जहां योग और भारतीय जनता पार्टी से रामरतन कुशवाहा, समाजवादी पार्टी से रमेश कुशवाहा तो वहीं बहुजन समाज पार्टी के चंद्रभूषण सिंह बुंदेला और गुड्डू राजा के साथ ही कांग्रेस से बलवंत सिंह लोधी को प्रत्याशी बनाया है। जिले में भाजपा और सपा से कुशवाहा प्रत्याशियों के साथ बसपा प्रत्याशी गुड्डू राजा को प्रबल उम्मीदवार माना जा रहा है। इसी बीच कुशवाहा प्रत्याशियों के जातीय समीकरण उस समय गडबडते नजर आ रहे हैं।

मुख्य सेक्टर प्रभारी बने पं.लीलाधर दुबे

ललितपुर। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष/पूर्व मुख्यमंत्री बहन कु.मायावती के निर्देश पर मुख्य सेक्टर प्रभारी झॉसी एवं चित्रकूट मण्डल लालाराम अहिरवार, मुख्य सेक्टर प्रभारी रविकान्त मौर्य, मुख्य सेक्टर प्रभारी बी.के.गौतम, मुख्य सेक्टर प्रभारी नरेश बाबू रावैर की संस्तुति पर अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष पं.लीलाधर दुबे उर्फ कुल्लू महाराज को झॉसी मण्डल का मुख्य सेक्टर प्रभारी बनाया गया है। इस आशय की जानकारी बसपा जिलाध्यक्ष दयाराम अहिरवार ने दी है। इस अवसर पर पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा पं.लीलाधर दुबे उर्फ कुल्लू महाराज का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। इस दौरान कैलाश नारायण कुशवाहा, संजय पड़वॉं आदि मौजूद रहे। संचालन तुलसीराम अहिरवार ने किया।

सपा प्रत्याशी रामविलास रजक ने किया नामांकन

ललितपुर। समाजवादी पार्टी से 227 महरौनी विधानसभा क्षेत्र के अधिकृत प्रत्याशी रामविलास रजक ने सोमवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। अपने समर्थकों के साथ कोविड नियमों का पालन करते हुये कलेक्ट्रेट पहुंचे सपा प्रत्याशी रामविलास रजक ने महरौनी के रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अपना नामांकन पत्र प्रस्तुत किया। नामांकन पत्र जमा होने के बाद बाहर आये रामविलास रजक ने कहा कि सत्तादल जहां जातिवाद की राजनीति कर रहा है तो वहीं समाजवादी पार्टी विकास कार्यों को लेकर चुनावी मैदान में है। उन्होंने कहा कि महरौनी क्षेत्र के किसानों को खुशहाल बनाने के लिए समाजवादी पार्टी कटिबद्ध है। कहा कि विधानसभा चुनाव 2022 में जनता के मत रूपी आशीर्वाद से सत्ता में यदि समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो सबसे पहले लोगों को संकल्प पत्र के अनुसार योजनाओं का संचालन कर लाभान्वित किया जायेगा।

बुजुर्गों के आशीर्वाद व युवाओं की ताकत से बनेगी सपा सरकार : रमेश कुशवाहा

कोविड प्रोटोकॉल और आचार संहिता का पालन करते हुए छह छह लोगों की टीमें ने किया जनसंपर्क

संवाददाता

ललितपुर। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रमेश कुशवाहा का आचार संहिता व कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए तृफानी जनसंपर्क जारी है। सोमवार को मोहल्ला सिद्ध एवं नेहरूनगर में पूर्व विधायक व प्रत्याशी रमेश कुशवाहा के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने छह छह लोगों की टोली बनाकर अलग अलग गलियों में जनता का आशीर्वाद लेकर वोट मांगे। मोहल्ला नेहरू नगर में लोगों ने उन्हें फूलमालाओं से लाद दिया। उन्होंने कहा कि जनता से मिले प्यार को वह

साहित्यानंद ने मनाई महात्मा गाँधी की 75 वीं पुण्यतिथि



संवाददाता

हाथरस। सासनी कस्बा में बुजुर्गों एवं कवियों की संस्था साहित्यानंद द्वारा शारद्विपता महात्मा गाँधी को उनकी 75 वीं पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि के साथ याद किया गया। उन्होंने कहा कि काव्यमोक्षी का आयोजन किया गया। सोमवार का कार्यक्रम के शुभारंभ में कवि वीरेंद्र जैन ने कहा कि महात्मा गाँधी के आदर्शों पर चल कर सत्य अहिंसा और प्रेम को अपना कर ही जीवन को खुशहाल बनाया जा सकता है। और कविता के माध्यम से बताया कि सत्य अहिंसा और प्रेम का घर धर

कन्या गुरुकुल में तीन दिवसीय सामवेद पारायण महायज्ञ का आयोजन



संवाददाता

हाथरस सासनी।आगरा अलीगढ़ रोड पर प्राचीन कंकाली मंदिर के पास स्थित कन्या गुरुकुल में तीन दिवसीय सामवेद पारायण महायज्ञ का आयोजन कराया है। इस यज्ञ से प्रकृति में शुद्धता आती है। समाज में पुत्र और पुत्री के बीच में अंतर करने वालों के लिए भी एक संदेश देने का काम पूरा होता है। इस परिवार ने लोगों को ये संदेश दिया है कि पुत्री भी उतनी ही जरूरी है जितना पुत्र। पुत्री की उन्नति भी पुत्र के बराबर ही होनी चाहिए। इस समाजसेवी प्रकाश वीर सिंह ने महायज्ञ के आयोजन को अपनी बेटी की खुशी में कराया। गुरुकुल की अलंकार डॉ पवित्रा ने बताया कि आज समाज में

विधायक निधि पर जनता हक है विधायक का नहीं : गुड्डू राजा

कोविड 19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए बसपा प्रत्याशी गुड्डू राजा ने किया नामांकन दाखिल

संवाददाता

ललितपुर। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी चंद्रभूषण सिंह बुंदेला उर्फ गुड्डू राजा ने नामांकन पत्र दाखिल करने बाद पत्रकारों से रुबरु होते हुए कहा कि बुंदेलखंड में सबसे पिछड़ा जिला है। ऐसे जो भी जनप्रतिनिधि व विधायक रहे, उन्होंने जनता कर हक पर डाका डाला है। उन्होंने कहा कि जो प्रतिनिधि बने हैं उन्हें विकास की चिंता नहीं रहती है, इस जिले में प्रथा चली आयी है कि जो भी विधायक रहे उन्होंने विधायक निधि से 20 से 30 प्रतिशत कमीशन लिया है, इस प्रथा को हम समाप्त करना है। उन्होंने कहा कि जिले में उद्योग नहीं है रोजगार नहीं है, लेकिन इस मुद्दे पर कोई जनप्रतिनिधि काम नहीं करता है। जाखलौन धौरौ क्षेत्र में पत्थर की खदानें बन्द पड़ी है लेकिन इस ओर किसी ने ध्यान दिया और लोग रोजगार नहीं में पलायन कर गए। उन्होंने



का काम करेगा। यह नामांकन ललितपुर को बुलंदियों तक ले जाएगा। गुड्डू राजा ने बताया कि ललितपुर में बहुत से पर्यटक स्थल है जहाँ पर अभी तक विकास कार्य रुके हुए हैं। ऐसे पर्यटक स्थल तक जाने वाली सड़कें गड्ढा युक्त है जिनको गड्ढा मुक्त किये जाने का कार्य किया जाएगा। ललितपुर में रुके विकास कार्यों को पूर्ण करा कर ललितपुर को बुलंदियों तक ले जाएगा। आज इन गांवों में चहुँचे गुड्डू राजा बसपा प्रत्याशी चंद्रभूषण सिंह बुंदेला (गुड्डू राजा) ने बताया कि ललितपुर वासियों के आशीर्वाद से सदर सीट से बसपा प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया है। जो नामांकन ललितपुर के विकास के दखाने खोलेंगा। यह नामांकन हर उम्मीद का विश्वास बढ़ायेगा गुड्डू राजा ने बताया कि यह नामांकन जनपद के हर जरूरतमंद लोगों की उम्मीद का विश्वास बढ़ायेगा। बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने





मुंबई में जापान और थाईलैंड के बीच एएफसी महिला एशियाई कप 2022 मैच के दौरान गोल करने के बाद जश्न मनाते जापान की युवा सुगासावा।

क्रिकहीरोज अवार्ड्स: क्रिकेट प्रतिभाओं की खोज कर किया गया सम्मानित

प्रफुल्ल कुमार राय

नई दिल्ली। हाल ही में वरुण अल समारोह में वितरित किए गए पहले क्रिकहीरोज अवार्ड्स ने सम्पूर्ण भारत में मौजूद जमीनी स्तर की क्रिकेट प्रतिभाओं की गहराई को अवगत कराया है। देश से करीब 17 शहरों और कस्बों के क्रिकेटर्स,

स्कोर, आयोजकों और टीमों ने खेल के प्रसार और लोकप्रियता को रेखांकित करते हुए 20 श्रेणियों में प्रस्कार प्राप्त किए। क्रिकहीरोज एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट प्रदर्शन विश्लेषण मंच है, जिसमें क्रिकेट की दुनिया भर में आधिकारिक भागीदार के रूप में कई घरेलू और अंतरराष्ट्रीय संघ और क्रिकेट बोर्ड्स के रूप में शामिल हैं।

क्रिकहीरोज में 1.1 करोड़ से अधिक क्रिकेटर्स का पंजीकरण है जिन्होंने कुल मिलाकर 20 लाख से अधिक मैच खेले हैं। 200 से अधिक क्रिकेट संघ क्रिकहीरोज को अपने आधिकारिक स्कोरिंग प्लेटफॉर्म के रूप में उपयोग कर रहे हैं।

लैंगर से मुलाकात तनावपूर्ण नहीं रही: सीए

सिडनी। क्रिकेट आस्ट्रेलिया ने इन रपटों को खारिज किया है कि मुख्य कोच जस्टिन लैंगर के साथ उसकी मुलाकात तनावपूर्ण रही और लैंगर को पद के लिये फिर से आवेदन देने को कहा गया है।

लैंगर का अनुबंध जून में समाप्त होना है। उन्होंने क्रिकेट आस्ट्रेलिया के मुख्य कार्यकारी निक हॉकली और हार्ड परफॉर्मंस मैनेजर बेन ओलिवर से पिछले सप्ताह मुलाकात की थी।

उसके बाद से स्थानीय मीडिया ने कहा कि यह बैठक तनावपूर्ण रही जब सीए ने उनसे इस पद के लिये फिर से आवेदन करने को कहा।

सीए ने एक बयान में इन



अटकलों को खारिज करते हुए मुख्य कोच जस्टिन लैंगर, क्रिकेट आस्ट्रेलिया के सीईओ निक हॉकली

और हार्ड परफॉर्मंस मैनेजर बेन ओलिवर के बीच हुई बैठक को लेकर फॉक्स स्पोर्ट्स की वेबसाइट पर जारी खबरें सही नहीं हैं।

इसमें कहा गया, "हम गोपनीय बातचीत पर टिप्पणी नहीं करते लेकिन तथ्यों को दुरुस्त करना जरूरी है।"

लैंगर को 2018 में गेंद से छेड़खानी मामले के बाद टीम का मुख्य कोच बनाया गया था। भारत के खिलाफ पिछले साल टेस्ट श्रृंखला में शर्मनाक हार के बाद उनको हटाये जाने की अटकलें लगाई जा रही थी लेकिन फिर आस्ट्रेलिया ने पहला टी20 विश्व कप और एशेज श्रृंखला 4-0 से जीती।

बेंगलुरु एफसी ने कैमरून के डिफेंडर याया बनाना से करार किया



मडगांव। बेंगलुरु एफसी ने कैमरून के डिफेंडर याया बनाना से इंडियन सुपर लीग के 2021-22 सत्र के अंत तक के लिये करार किया है। तीस वर्ष के बाना हाल ही में जोर्डन प्री लीग क्लब शाबाब अल ओडीन के लिये खेले थे। वह टीम में गाबोन के डिफेंडर यरोंडु मुसावू किंग की जगह लेंगे जो चोटिल है। बाना अंडर 20 और सीनियर स्तर पर कैमरून के लिये खेल चुके हैं। उन्होंने 2019 अफ्रीकी कप आफ नेशंस में गोल भी किया था।

आरिफ खान शीतकालीन ओलंपिक के लिये रवाना

नयी दिल्ली। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक खेलों में भारत के इकलौते प्रतिनिधि स्कीअर आरिफ खान दल प्रमुख हरजिंदर सिंह और सहयोगी स्टाफ के साथ रवाना हो गए हैं। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरिंदर बत्रा ने सोमवार को खानों से पहले उन्हें शुभकामनाएं दीं।

आरिफ दो स्पर्धाओं में भाग लेंगे और शुरुआत से शुरू हो रहे खेलों में उनका लक्ष्य शीर्ष 30 में जगह बनाना है।

बत्रा ने बताया कि भारतीय टीम 19 फरवरी को लौटेगी।

जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में रहने वाले आरिफ बीजिंग में स्लालोम और जाइंट स्लालोम वर्ग में भाग लेंगे जो



13 और 16 फरवरी को खेले जायेंगी। 31 वर्ष के आरिफ ने सापोरो में

एशियाई शीतकालीन खेलों में भी भाग लिया था।

आईओए ने भारतीय आइस हॉकी संघ के महासचिव हरजिंदर को दल प्रमुख के रूप में भेजा है। हाल ही में टारगेट ओलंपिक पोजिशन योजना में जगह बनाने वाले आरिफ ने कहा कि सैंटा कैटरीना में अभ्यास से उन्हें काफी मदद मिली है।

उन्होंने कहा, "मैं कुछ साल से काफी मेहनत कर रहा हूँ और शीर्ष 30 में आना भी मेरे लिये पदक की तरह होगा।"

अंडर 19 विश्व कप : बांग्लादेश को हराकर पाकिस्तान पांचवें स्थान के प्लेआफ में

कूलिज (एटिंगा)। हसीबुल्लाह खान के अर्धशतक की मदद से पाकिस्तान ने अंडर 19 विश्व कप के मुकाबले में बांग्लादेश को छह विकेट से हरा दिया जबकि बांग्लादेश के लिये आरिफुल इस्लाम का शतक बेकार गया। बांग्लादेश की पारी का आकर्षण इस्लाम रहे जिन्होंने 12वें ओवर में आकर मोर्चा संभाला जिस समय टीम ने 23 रन पर तीन विकेट गंवा दिये थे।

पिछली दो पारियों में इस्लाम दोहरे अंक तक भी नहीं पहुंच सके थे लेकिन इस मैच में फॉर्म में लौटते हुए छक्का लगाकर अर्धशतक पूरा किया। दूसरे छोर से उन्हें सहयोग नहीं मिल सका। पाकिस्तान के लिये मेहरान मुमतजाज ने 10 ओवर में 16 रन देकर तीन विकेट लिए। इस्लाम ने अवेस अली को एक ओवर में तीन छक्के जड़े। उन्होंने 49वें ओवर में अपना शतक 118 गेंदों पर पूरा किया। अगली गेंद पर वह हालांकि आउट हो गए।



जवाब में पाकिस्तान के लिये मोहम्मद शहजाद और हसीबुल्लाह ने अच्छी शुरुआत करके 19 ओवर में 76 रन जोड़े। खान ने अपनी पारी में चार चौके और चार छक्के लगाये और वह 78 रन बनाकर आउट हुए। उस

समय उनकी टीम को जीत के लिये 36 रन की जरूरत थी। अब्दुल फसीह ने नाबाद 22 रन बनाकर टीम को 21 गेंद बाकी रहते जीत तक पहुंचाया। पाकिस्तान अब गुरुवार को श्रीलंका से पांचवें स्थान का प्लेआफ मुकाबला खेलेगा जबकि बांग्लादेश सातवें स्थान के मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका का सामना करेगा। प्लेट वर्ग के फाइनल में संयुक्त अरब अमिरात ने आयरलैंड को आठ विकेट से हराया।

अंडर 19 विश्व कप सेमीफाइनल में भारत के सामने आस्ट्रेलियाई चुनौती

रवि शंकर तिवारी

कूलिज (एटिंगा)। मैदान पर अपने प्रतिद्वंद्वियों को और मैदान के बाहर कोरोना वायरस को हराने वाली भारत और आस्ट्रेलिया की दिग्गज टीमों अंडर 19 विश्व कप के सेमीफाइनल में यहां बुधवार को आमने सामने होंगी।

कोरोना महामारी के कारण भारत की तैयारियां काफी बाधित हुईं। पिछले दो साल में कोई राष्ट्रीय शिबिर या टूर्नामेंट नहीं था और हाल ही में सिर्फ एशिया कप खेलकर टीम यहां आई थी।

चार बार की चैंपियन भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 45 रन से हराकर टूर्नामेंट में आगाज किया। इसके बाद हालांकि कई खिलाड़ियों के कोरोना संक्रमित पाये जाने के बाद आयरलैंड के खिलाफ बमुश्किल 11 खिलाड़ी जुट सके। आयरलैंड के खिलाफ दूसरे ग्रुप मैच में पांच खिलाड़ी उपलब्ध नहीं थे। कप्तान यश धुल, उपकप्तान शेख



रशीद, आरुध्य यादव, मानव पारख और सिद्धार्थ यादव कोरोना वायरस की चपेट मर आ गए थे। ये पांचों आयरलैंड और युगांडा के खिलाफ नहीं खेल सके जिसके बाद बीसीसीआई को वैकल्पिक खिलाड़ी भेजने पड़े। युगांडा के खिलाफ छह रिजर्व खिलाड़ियों को मैदान पर उतारा गया। भारतीय टीम ने हालांकि आयरलैंड और युगांडा दोनों को हराया और क्वार्टर फाइनल में बांग्लादेश को मात दी।

अब भारत के पास पूरी मजबूत टीम है और निशांत सिंधू भी संक्रमण से उबर चुके हैं।

भारत को हालांकि आखिरी ओवरों में अपनी बल्लेबाजी में सुधार करना होगा। उससे पहले भारत ने आयरलैंड के खिलाफ पांच विकेट पर 307 और युगांडा के खिलाफ 405 रन बनाये जो अफ्रीकी टीम के खिलाफ उसकी सबसे बड़ी जीत थी। अब सामने आस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम है। भारत का मनोबल इस बात से बढ़ होगा कि कोरोना से

जुड़ते हुए भी सारे मैच जीतकर वह अंतिम चार में पहुंचा है। भारत लगातार चौथी बार सेमीफाइनल खेलेगा। भारत के पास हरनूर सिंह, अंगकृष्ण रघुवंशी, राज बाबा के अलावा धुल और रशीद जैसे बल्लेबाज हैं। धुल ने पहले मैच में 82 रन बनाये थे।

गेंदबाजी में रवि कुमार ने बांग्लादेश के खिलाफ पांच ओवर में 14 रन देकर तीन विकेट चटकाने थे। तेज गेंदबाज राजवर्धन हंगोरकर, स्पिनर विकी ओस्तवाल और कौशल

तांबे के साथ मध्यम तेज गेंदबाज बाबा पर नज़रें होंगी।

दो बार की चैंपियन आस्ट्रेलिया ने क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान को हराया। उसके पास शानदार सलामी बल्लेबाज टिम वीली है जिन्होंने अब तक बेहतरीन प्रदर्शन किया है। पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने 71 गेंद में 97 रन बनाये और भारत को उनके बल्ले पर अंकुश लगाना होगा।

भारत ने अभ्यास मैच में आस्ट्रेलिया को हराया था।

टीमों: भारत : यश धुल (कप्तान), अंगकृष्ण रघुवंशी, हरनूर सिंह, राज बाबा, कौशल तांबे, दिनेश बाना, निशांत सिंधू, विकी ओस्तवाल, राजवर्धन हंगोरकर, वासु वत्स, रवि कुमार।

आस्ट्रेलिया: कूपर कोनोली (कप्तान), कैपबेल केलावे, टिम वीली, एडन काहिल, कोरे मिलर, जैक सिनफ्रील्ड, टोबियास पनेल, विलियम साल्जमैन, जैक निसबेट, लाचलान शॉ, टाम व्हाइटनी।

रेंजर्स एफसी ने अंतरराष्ट्रीय मिडफील्डर आरोन रैमसे के साथ किया करार

एडिनबर्ग। रेंजर्स एफसी ने सीजन के अंत तक जुवेंटस से ऋण पर वेल्स के अंतरराष्ट्रीय मिडफील्डर आरोन रैमसे के साथ करार किया है।

रैमसे ने अपने करियर की शुरुआत कार्डिफ सिटी से की थी और तब वह उनके सबसे कम उम्र के खिलाड़ी थे। 2008 में कार्डिफ सिटी को एएफ कप के फाइनल में पहुंचने में मदद करने के बाद, उन्होंने आर्सेनल में कदम रखा।

आर्सेनल के साथ, उन्होंने 2014 एएफ कप फाइनल में एलन



मैकग्रेगर के हल सिटी के खिलाफ जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके एक साल बाद आर्सेनल ने

लिए 11 साल के असाधारण समय में 371 मैच खेले। रेंजर्स के साथ जुड़ने पर रैमसे ने कहा, मैं रेंजर्स जैसे क्लब में शामिल होकर वास्तव में प्रसन्न हूँ। क्लब के साथ अभी और मई के बीच आगे देखने के लिए बहुत कुछ है।

उन्होंने कहा, मेरे पास मेज पर कई प्रस्ताव थे, लेकिन यूरोपीय फुटबॉल और हर दूसरे हफ्ते 50,000 प्रशंसकों के सामने खेलने का मौका इस क्लब के अलावा कहीं नहीं मिलता।

प्रीमियर लीग क्लब एवर्टन ने मिडफील्डर डेले अल्ली के साथ किया करार

लंदन। प्रीमियर लीग क्लब एवर्टन ने टोटनहम हॉटस्पर से मिडफील्डर डेले अल्ली के साथ करार पूरा कर लिया है। डेले अल्ली जून 2024 के अंत तक बाई साल के अनुबंध पर एवर्टन में शामिल हुए हैं।

फरवरी 2015 में शामिल होने के बाद इंग्लैंड के अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी अल्ली ने टोटनहम हॉटस्पर के लिए 269 मैच खेले हैं और 67 गोल किये हैं। डेले संभावित रूप से अगले मंगलवार को न्यूकैसल यूनाइटेड में प्रीमियर लीग मैच में एवर्टन के लिए शुरुआत कर सकते हैं।

25 वर्षीय, अल्ली ने इंग्लैंड के लिए 37 मैच खेले हैं और वह 2018 विश्व कप सेमीफाइनल में इंग्लिश टीम के एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी थे।

एवर्टन में शामिल होने पर, डेले ने एक आधिकारिक विज्ञापन में कहा, मुझे एक महान और इतिहास के एक विशाल क्लब एवर्टन के साथ करार करने पर खुशी है। मैं क्लब के साथ



शुरुआत करने के लिए उत्सुक हूँ और अपने पहले मैच की ओर प्रतीक्षा नहीं कर सकता।

उन्होंने आगे कहा, मैं टीम की मदद करने और नए मैनेजर फ्रैंक लैम्पार्ड के साथ काम करने के अवसर की उम्मीद कर रहा हूँ। मिडफील्डर डेले ने 2016 यूरोपीय चैंपियनशिप और 2019 में राष्ट्र लीग फाइनल में इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने 2017/18 में 20 प्रीमियर लीग मैचों में नौ गोल किये।

प्रीमियर लीग में नए 11 कोरोना संक्रमित मामले सामने आए

लंदन। प्रीमियर लीग में सोमवार, 24 जनवरी और रविवार, 30 जनवरी के बीच, 1,947 खिलाड़ियों और क्लब के कर्मचारियों के कोविड-19 टेस्ट किये गए, जिनमें नए 11 कोरोना संक्रमित मामले सामने आए।

प्रीमियर लीग ने एक आधिकारिक बयान में कहा, इस रिपोर्टिंग अवधि में कुल परीक्षण संख्या कम है क्योंकि स्कॉटिश प्रीमियर लीग के मिड-सीजन प्लेयर ब्रेक के कारण कई खिलाड़ी मैदान से दूर हैं।

यह भी पुष्टि की गई कि 85 प्रतिशत खिलाड़ियों ने कोविड टीकाकरण खुराक प्राप्त कर ली है। विज्ञापन में कहा गया है, लीग खिलाड़ियों और क्लब के कर्मचारियों के बीच टीकाकरण को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ सरकार के सार्वजनिक स्वास्थ्य टीकाकरण संदेश को बढ़ावा देने के लिए क्लबों के साथ काम करना जारी रखे हुए है।

मिड-सीजन ब्रेक के बाद, प्रीमियर लीग की शुरुआत शनिवार, 5 फरवरी से होगी। वर्तमान में, मैनचेस्टर सिटी प्रीमियर लीग अंकतालिका में शीर्ष पर है और उसके बाद लिंकरन है।



मुंबई में वियतनाम के खिलाफ एएफसी महिला एशियाई कप 2022 मैच जीतने के बाद जश्न मनाते चीन की वांग शुआंग।